

1 करोड़ से अधिक कैश और एके-47 समेत भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त

■ **सर्चिंग ऑपरेशन में जमीन के अंदर मिला नक्सलियों का डंप, ग्रेनेड लॉन्चर, जन्रेटर जैसे सामान**

नारायणपुर। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर में मंगलवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अबुझमाड़ इलाके के जंगल में नक्सल डंप बरामद हुआ है। जिसमें छिपाकर रखे गए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, ऑटोमैटिक हथियार, देशी बीजीएल रॉकेट लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई जिला नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसए के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान की गई है। जानकारी के मुताबिक, जवानों की संयुक्त टीम ने अबुझमाड़ क्षेत्र



के जंगल में सच ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान के पास नक्सल डंप मिला। जांच करने पर मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। जवानों की इस कार्रवाई में नक्सल डंप से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। संयुक्त कार्यवाही में कुल 1,01,64,000 रुपये कैश और

एके-47, एसएलआर, इंसास, 303 रायफल और इनके कारतूस बीजीएल, सेल , इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर, नक्सल वर्दी, बैटरी के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया है।

क्षेत्र में लगातार सुरक्षाबलों की कार्रवाई जारी है। बोते एक महीने में अबुझमाड की जंगलों में छिपाए नक्सली सामान और

बंदूक मिल रहे हैं। बरामद सामग्री में तीन,च-47 रायफल, तीन 3 स्क्र रायफल, दो 303 रायफल और एक 315 बोर रायफल शामिल हैं। इसके अलावा एके – 47 के 5 मैग्जीन और 113 जिंदा कारतूस, एसएलआर रायफल के 13 मैग्जीन और 182 जिंदा कारतूस, इंसास रायफल का 1 मैग्जीन, 303 रायफल के 2 मैग्जीन और 45 जिंदा कारतूस, जबकि 315 रायफल का 1 मैग्जीन और 41 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 2 नग 12 बोर बंदूक, 2 देशी कट्टा, 19 नग 12 बोर के जिंदा कारतूस और 1 एयर गन भी बरामद हुई। बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है, जिसमें 132 बीजीएल सेल, 2 बीजीएल, 14 बीजीएल कार्टेज,

12 एसएमजी कार्टेज, 8 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 6 बंडल कॉर्डेक्स वायर, लगभग 5 किलो सोरा और करीब 3 किलो व्हाइट पाउडर शामिल है। संचार उपकरणों में 1 मोटोरोला सेट, 6 वॉकी-टॉकी बॉओफंग, 4 सेट रेडियो सेल और 2 बंडल बिजली वायर भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी सुरक्षा बलों ने बरामद की है। बताते चलें कि नारायणपुर एसपी रोबिनसन गुड्डिया ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 270 हथियार बरामद किए जा चुके हैं, जो नक्सल नेटवर्क पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह आंकड़ा बताता है कि क्षेत्र में विश्वास, शांति और विकास की प्रक्रिया लगातार गति पकड़ रही है।

संयुक्त कोयला मजदूर संघ ने मांगों को लेकर पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा



कोरबा। कोरबा में संयुक्त कोयला मजदूर संघ (एटक) ने श्रमिक हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। संघ ने महाप्रबंधक, कोरबा क्षेत्र, एसईसीएल के माध्यम से यह ज्ञापन 12 मई 2026 को भेजा है। मांग पत्र में श्रम संहिताएं वापस लेने, गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई, न्यूनतम वेतन 26 हजार करने समेत कई मांगों शामिल हैं। क्षेत्रीय सचिव बी. धर्मा राव द्वारा भेजे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि श्रम संघ मजदूर हित, लोक हित, उद्योग हित व देश हित में मांग पत्र प्रस्तुत कर रहा है। संघ ने प्रधानमंत्री से मांग पत्र को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई की अपील की है। श्रमिक विरोधी श्रम संहिताएं वापस हों।

संघ ने नई श्रम संहिताओं को श्रमिक विरोधी बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। गिरफ्तार श्रमिकों की तत्काल रिहाई एवं उन पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। वर्तमान महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये

प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग रखी गई। आठ घंटे कार्य दिवस लागू हो। आठ घंटे कार्य दिवस एवं उससे अधिक काम करने पर दोगुना ओवरटाइम लागू करने की मांग की गई। संविदा श्रमिकों को समान वेतन एवं स्थायी रोजगार देने की मांग उठाई गई। एलपीजी एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग की गई। मांग पत्र अध्यक्ष मनीष सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष सिंह एवं सचिव बी. धर्मा राव के नेतृत्व में धर्मा गया है। श्रमिक नेता बी धर्मा राव ने बताया कि श्रमिकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर आज वह प्रदर्शन किए हैं और आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। श्रमिक नेता मनीष मुखर्जी ने बताया कि संघ ने कहा कि कोयला उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण जरूरी है। यदि मांगों पर जल्द विचार नहीं हुआ तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघ ने प्रधानमंत्री से सहयोग की अपेक्षा जताई है।

जीपीएम में कोर्ट अवन-आवासीय परिसर का शिलान्यास

गौरै ला -पेंड्रा -मरवाही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने मंगलवार को जिले में न्यायिक अधोसंरचना के महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। इसके तहत पेंड्रारोड और मरवाही में नई न्यायिक सुविधाओं की आधारशिला रखी गई। पेंड्रारोड में डीआरडीए कार्यालय के पीछे न्यायिक कर्मचारियों और न्यायाधीशों के लिए आवासीय परिसर बनेगा। वहीं, मरवाही में उद्यानिकी कार्यालय के समीप



नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का निर्माण होगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायिक सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति रजनी दुबे भी आभासी माध्यम से उपस्थित रहें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी

के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनना चाहिए। पेंड्रारोड में कुल 26 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इनमें 8 जी टाइप, 10 एच टाइप और 8 आई टाइप आवास शामिल हैं।

मरवाही में नवीन सिविल कोर्ट भवन बनने से क्षेत्र की न्यायिक सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे लोगों को बेहतर न्यायिक सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति रजनी दुबे भी आभासी माध्यम से उपस्थित रहें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी

कबीरधाम में साइकिल से ऑफिस पहुंचे एसपी धर्मेन्द्र सिंह

कबीरधाम। कबीरधाम में ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए कबीरधाम पुलिस ने एक प्रेरक पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने अपने निवास से साइकिल चलाकर कार्यालय पहुंचकर इसका उदाहरण पेश किया। उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण संबंधी आह्वान से प्रेरित है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अब केवल सरकारी नीति नहीं, बल्कि हर नागरिक की



सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में बदलाव से ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान संभव है। पुलिस अधीक्षक ने उन अधिकारियों-कर्मचारियों से अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की।

जिनका निवास कार्यालय के आसपास है, वे पैदल या साइकिल से कार्यालय पहुंचें। उन्होंने सुझाव दिया कि हर अधिकारी-कर्मचारी सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल या पैदल कार्यालय आने का संकल्प लें। इससे ऊर्जा बचत के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा।

इस पहल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और उप पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव भी शामिल हुए। उनके साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। सभी ने साइकिल के कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया। इस सामूहिक प्रयास से पर्यावरण जागरूकता को बल मिला है

जिले से नक्सलवाद का साया खत्म

मोहला-मानपुर। जिले में

छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहलाने वाले तेंदूपत्ता का संग्रहण पहले की तरह जारी है। जिले में 39 समितियों के तहत संग्रहण हो रहा है। डी एफ ओ ने ग्रामीणों से जंगल में जंगली-जानवरों से सुरक्षित रहकर तेंदूपत्ता तोड़ने की अपील की है। बता दें कि मोहला-मानपुर जिला प्रदेश का बड़ा तेंदूपत्ता संग्राहक जिला है, जहां से हर साल तेंदूपत्तों की बड़ी खेप निकलती है। तेंदूपत्ता का ये सीजन इस लिहाज से भी खास है कि अब जिले से नक्सलवाद का साया खत्म हो चुका है। तेंदूपत्तों में आगजनी करने और लेवी के लिए ठेकेदारों को डराने धमकाने वाले नक्सली गतिवि में जा चुके हैं। लिहाज़ा इस बार बेखौफ तेंदूपत्ता संग्रहण हो रहा है। जिले

बेखौफ तेंदूपत्ता का संग्रहण जारी



के डीएफओ दिनेश पटेल के मुताबिक, राजनांदगांव यूनियन अंतर्गत मोहला मानपुर जिले में तेंदूपत्ता का संग्रहण होता है। पूरे यूनियन में 80 हजार तेंदूपत्ता मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य है, जिसमें से 60 हजार मानक बोरा संग्रहण अकेले मोहला मानपुर जिले से होता है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 39 समितियां बनी हैं, जो संग्रहण करा रही हैं। बारिश के चलते कुछ

समितियों में संग्रहण चालू नहीं हो सका है, लेकिन अब मौसम अनुकूल है जल्द शेष में भी संग्रहण चालू हो जाएगा। डीएफओ के मुताबिक, बारिश का आंशिक प्रभाव तेंदूपत्ता पर हुआ है, जिससे कहीं-कहीं कुछ पत्ते बारिश में खराब हुए हैं। आम तौर पर तेंदूपत्ता सीजन में माओवादी सक्रिय रहते थे और पत्तों में आगजनी जैसी घटनाओं को वे अंजाम देते थे। डी एफ ओ ने कहा कि इस बार नक्सल खोफ वाली कोई बात नहीं है और नक्सलियों द्वारा तेंदूपत्तों में आगजनी किए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लोग बेखौफ होकर तेंदूपत्ता संग्रहण करेंगे और ऐसे में इस बार अधिक से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण जिले में होगा।

बालोद में 20 अप्रैल से लापता मूक-बधिर युवक, परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार

बालोद। जिले के राजहरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 निवासी डोमेंद्र कुमार साहू 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। उनका परिवार काफी परेशान है और पुलिस में शिकायत के बावजूद उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। परिवजनों ने अब प्रशासन से बेटे की तलाश के लिए गुहार लगाई है। डोमेंद्र के माता-पिता घर में काफी परेशान हैं। परिवार ने बताया कि डोमेंद्र बोल और सुन नहीं सकते, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। लापता युवक की बुआ उमा भाई

ने आरोप लगाया कि पुलिस ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति लापता होता तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती। लेकिन गरीबों की आज सुनने वाला कोई नहीं है। उमा भाई और उनके भाई प्रशासन के पास उम्मीद लेकर आए हैं। डोमेंद्र के चाचा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वह दुर्ग रेलवे स्टेशन तक जाते हुए दिखे हैं। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले पर राजहरा के नगर पुलिस अधीक्षक विकास पतले ने जानकारी दी।

जगदलपुर में नर्स दिवस पर केक कटिंग



है। आज के दिन नर्सों के सेवाभाव को विशेष रूप से सलाम किया जाता है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। इंटरनेशनल कार्डिसल ऑफ नर्सेस ने हर साल 12 मई को यह दिन मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस स्वास्थ्य क्षेत्र के चिकित्सा कार्यों में नर्सों के महत्व को दर्शाता है। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सीएससी और पीएचसी की नर्सों ने इस दिन को खास बनाया। उनका 24 घंटे का

समर्पण मरीजों के लिए अमूल्य है। लेडी विद लैप के नाम से मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महान नर्स थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। एक समृद्ध परिवार से होने के बावजूद, उन्होंने लोगों की सेवा के लिए नर्सिंग का पेशा अपनाया। वर्ष 1854 में न्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने दिन-रात बिना रुके सेवा की। वह घायलों को देखने के लिए रात को एक लैंप लेकर निकलती थीं। इसी कारण उन्हें लेडी विद लैप के नाम से जाना जाने लगा। उनका समर्पण आज भी नर्सों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे की बढहाल सड़क से लोग परेशन

सूरजपुर। अंबिकापुर बनारस स्टेट हाइवे में खड्डगांव मार्ग बदहाल है। गोहगड नाला से केरता चौक तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालत ये है कि सड़क में गड्डे है या गड्डे में सड़क है ये पता नहीं चल पा रहा है। सड़क की बदहाली और लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जीशान अहमद खां ने अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क के गड्डे भरना शुरू कर दिया। जीशान खान अपने साथी राकेश मित्तल, शम्भू मरावी व महबुब्खा के साथ मिलकर गाड़ी से क्रेशर डस्ट लेकर पहुंचे और गड्डों में भरना शुरू किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि गोहगड नाला से केरता चौक तक सड़क की हालत बहुत खराब है। बड़ी बड़ी ट्रैकें इस सड़क से गुजरती है, जिससे सड़क में बड़े बड़े गड्डे हो गए हैं, हमेशा धूल उड़ती है। गड्डों के कारण आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है। महिलाओं, बच्चों को परेशानी होती है। इसी वजह से वे गड्डों को भरने का काम कर रहे हैं। कई बार प्रशासन को सड़क की बदहाल स्थिति के बारे में बताया गया।

देवेंद्र यादव और यूथ कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर

दुर्ग। बेमेतरा में 300 गौवंशों की कथित मौत के मामले को लेकर हुए युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। बेमेतरा के उमलापुर-झिरिया में बोते हफ्ते कथित रूप से 300 से ज्यादा गोवंशों की दर्दनाक मौत हुई। इसके विरोध में यूथ कांग्रेस ने ग्राम झिरिया में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा, पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने विधायक एवं कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम और गौसेवा आयोग के अध्यक्ष की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली।

उर्स जुलूस के दौरान मारपीट के आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने उर्स जुलूस निकाला था। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व जुलूस में मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर डराने लगे। शहर में उस दिन कई जगह जुलूस निकाले गए, जिसमें से तालाफारा और सिविल लाइन क्षेत्र में उर्स जुलूस में हथियार दिखाकर दहशत फैलाने की घटना सामने आई। बिलासपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हथियार लहराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना तालाफारा की है जहां उर्स जुलूस की एक टोली मारगपारा चौक से गुजर रही थी। इसी दौरान आरोपी अब्दुल अजीम खान बीच में चापड़नुमा धारदार हथियार लेकर लोगों के हाथ लहराते हुए मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे मौके से पकड़कर कार्रवाई की है।वहीं दूसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां उर्स के दौरान घोड़ादाना स्कूल तारबहार से संदल और चाचद की दूस्री टोली निकली थी। इस दौरान पुलिस लाइन के पास मामूली विवाद होने पर आरोपी हर्ष खांडे ने बड़ा चाकू लहराकर लोगों को डराना शुरू कर दिया।

अवैध शराब बिक्री से पूरा गांव बढनाम, ज्ञापन सौंपा

धमतरी। जिले में एक गांव ऐसा है, जहां गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नशे की चपेट में हैं। हम बात कर रहे हैं कुरुद विकासखंड के ग्राम कल्ले की, जो आज एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है, जिसे सुनकर शासन और प्रशासन दोनों को शर्मसार होना चाहिए।इस गांव में पिछले 10 सालों से अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। आलम ये है कि गांव की गलियों में शराब की नदियां बह रही हैं और नशे में धुत लोग सरेंआम गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं, लेकिन इस नशे की सबसे बड़ी कीमत गांव के युवक और युवतियां चुका रहे हैं। कल्ले गांव के माता-पिता की आंखों में आज चिंता की गहरी लकीरें हैं। वजह ये है कि उनसे बच्चों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे। जब भी गांव के किसी युवक के लिए रिश्ता लेकर ग्रामीण दूसरे गांव जाते हैं तो सामने से एक ही जवाब मिलता है कि जिस गांव में शराब का तांडव हो वहां हम अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। वहीं गांव में लड़के पक्ष के लोग लड़की देखने आते हैं तो लड़कें पक्ष के लोग भी यही कहकर लड़की मांगने से साफ इनकार कर देते हैं।

विकास के दावे की खुली पोल, पानी को तरसता गांव

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसी में से एक है नारायणपुर जिले का कारकानार गांव, जहां के ग्रामीण पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इतना ही नहीं गांव में बिजली के पोल और तार तो लगा दिए गए, लेकिन आज तक बिजली नहीं पहुंची है। इस मामले में कलेक्टर नम्रता जैन ने शुद्ध पानी के साथ ही मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। दरपंज जरूर लगाया गया है पर उसमें से पानी नहीं आता, जिसके कारण महिलाएं रोजाना 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाने जाती है।ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कल जीवन मिशन के तहत नल लगाने और प्लेटफॉर्म बनाने का काम, तो कर दिया गया पर वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया।

भिलाई की सुष्मिता ने ऐसे पाई सफलता, बनी आईएफएस अफसर

दुर्ग। भिलाई की सुष्मिता सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सुष्मिता सिंह ने डूब्रस परीक्षा में ऑल इंडिया में 32वीं रैंक हासिल की। सुष्मिता की सफलता की कहानी संघर्ष, धैर्य और जुनून की मिसाल है।

उन्होंने साल 2019 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कई बार मेंस परीक्षा पास करने के बावजूद अंतिम चयन नहीं हो पाया, लेकिन पिता ने हिम्मत दी। लगातार 6 वर्षों तक मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर आखिरकार अपने छटे



प्रयास में यह मुकाम हासिल किया। अब अगस्त महीने में वह मसूरी में तीन माह के प्रशिक्षण के लिए जाएंगी, जिसके बाद रैंक के अनुसार कैडर आवंटित होगा। सुष्मिता की शुरुआती पढ़ाई राजनांदगांव और बिलासपुर में हुई, जबकि उन्होंने डीपीएस भिलाई से स्कूली शिक्षा पूरी कर यूपीएस देहरादून से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। नौकरी

छोड़कर उन्होंने पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी पर फोकस किया। सुष्मिता सिंह के पिता भानु प्रताप सिंह वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

परिवार में वन सेवा का माहौल होने के कारण बचपन से ही उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। सुष्मिता ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता,

दोस्तों, योगा और मेडिटेशन को दिया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी यह सफलता आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। सुष्मिता की इच्छा है कि उन्हें छत्तीसगढ़ में सेवा करने का अवसर मिले। सुष्मिता की मां हिना सिंह ने कहा कि बेटी ने पूरे परिवार को गर्व का एहसास कराया। हमारे सपनों को बेटी ने पूरा किया। हिना सिंह बताती हैं कि उनकी बेटी परिवर से बहुत स्नेह करती है। हमेशा उसे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। आज हमारी बेटी ने परिवार का

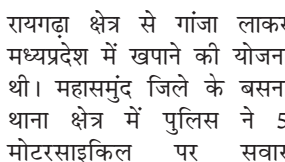
सपना पूरा कर दिया है। हिना सिंह बताती हैं कि उन्होंने बेटी को काफी अच्छे माहौल में पढ़ाया। सुबह जब बेटी सोकर उठती थी तो सबसे पहले उसे किताब पढ़ने को कहा जाता था, और एम्पल खिलती थी। उसके बाद ही वह दूसरा काम करती थी। पेड़ों के बीच गाना गाकर स्पेलिंग याद करायी करती थी। ब्लैकबोर्ड में उस कहती थी कि मुझे पढ़ाओ, तो ये इसे काफी पसंद था। हमेशा से ही वह पढ़ने में फर्स्ट आती थी। हमेशा खुशी से पढ़ाई करती थी। पढ़ाई को लेकर इच्छा शक्ति मजबूत है सुष्मिता के पिता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि साल 2024 में वे वन सेवा से रिटायर हुए।

कपड़ा फेरीवालों की आड़ में गांजा तस्करी

महासमुंद। रायपुर रेंज पुलिस को गांजी तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। महासमुंद और धमतरी में पुलिस ने 12 अंतरराज्यीय गांजा तस्करी को गिरफ्तार किया है।आरोपियों के पास से पुलिस ने 378 किलो गांजा जब्त किया है। जबत गांजा के अनुमानित कीमत 1 करोड़ 89 लाख 03 हजार रुपये बताई गई है। गांजा तस्करी के इस मामले में 11 दूधौलर भी जब्त किए गए हैं। कुल जबरन संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ 98 लाख 05 हजार रुपये आंकी गई है। रायपुर रेंज पुलिस के अनुसार तस्करी ने गांजा तस्करी के लिए बेहद शक्तिर तरीका अपनाया था। आरोपी बाइक में कपड़ा फेरीवाले (स्ट्रीट वेंडर्स) बनकर घूमते थे।



गाड़ी के पीछे ऊपर से कपड़े के ढेर दिखते थे लेकिन इन कपड़ों के ढेर के बीच में विशेष लोहे का कम्पार्टमेंट बनाकर गांजा तस्करी की जाती थी। इससे पहले भी एम्बुलेंस, केला परिवहन, मूवर्स एंड पैकर्स, ऑटो, बस ट्रेवल्स और ट्रेन के जरिए गांजा तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। अब कपड़ा फेरीवालों के रूप में गांजा तस्करी का जो रही थी। पूछछाछ में आरोपियों ने बताया कि ओडिशा के बालिगुड़ा और तितरी



रायगढ़ा क्षेत्र से गांजा लाकर मध्यप्रदेश में खपाने की योजना थी। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों को पकड़ा। सभी आरोपी कपड़ा विक्रेता बनकर गांजा तस्करी कर रहे थे। बाइक की पिछली सीट पर लोहे की जालीदार संरचना बनाकर गांजा छिपाया गया था। इसके अलावा एक अन्य मामले में 23 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कोमाखान पुलिस ने टेमरी जांच नाका पर होंडा साइन मोटरसाइकिल से 9 किलो 60 ग्राम गांजा जब्त किया।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री 13 एवं 14 मई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर

रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान 13 एवं 14 मई 2026 को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं हितग्राहियों से संवाद करेंगे। श्री पासवान 13 मई को राज्य स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कोशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही वे बीबी-जी राम जी से संबंधित तैयारियों एवं ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। श्री पासवान प्रवास के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संगोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान 14 मई को ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं नवाचारों का अवलोकन कर लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे स्व-सहायता समूहों की महिलाओं एवं विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से सीधे संवाद करेंगे।

बिलासपुर की शिविका पांडेय बनीं राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियन, जीता गोल्ड

रायपुर। शिविका पांडेय बनीं राज्य स्तरीय स्केटिंग चैंपियनरायपुर के सरोना स्थित निजी पब्लिक स्कूल के स्केटिंग ग्राउंड में 9 एवं 10 मई 2026 को प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रोलर स्पोर्ट्स रैंकिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर की होनहार खिलाड़ी शिविका पांडेय ने अपनी प्रतिभा और अदम्य साहस का लोहा मनवाते हुए राज्य स्तरीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। शिविका ने 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के ट्वॉय इनलाइन स्केट स्पर्धा में हिस्सा लिया। 9 मई को आयोजित 400 मीटर रेस के दौरान वे गंभीर रूप से चोटिल हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और घायल अवस्था में ही रेस पूरी कर कांस्य पदक जीता। अगले ही दिन, उसी चोट और दर्द के बावजूद, शिविका ने 200 मीटर रेस में असाधारण प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और अपने आयु वर्ग की ओवरऑल चैंपियन बनीं।

सुशासन तिहार 2026 : सिमड़ा शिविर में सुगन्ती तिकी को मिली ट्राइसाइकिल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान करने में निराकरण किया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम सिमड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में एक दिव्यांग हितग्राही को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई तथा 3 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ग्राम सिमड़ा की सुगन्ती तिकी को ट्राइसाइकिल मिलने से अब उनके आवागमन में सुविधा होगी और उन्हें दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं डोम, नूपर्पति और रामेश्वर साय को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए। सुगन्ती तिकी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्राइसाइकिल मिलने से उनका जीवन काफी आसान हो जाएगा। वहीं पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन की इस संवेदनशील पहल के लिए धन्यवाद दिया।

खुटपाली व्यपवर्तन योजना के कार्यों के लिए 147.48 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बलरामपुर-रामानुजगढ़ जिले के विकासखण्ड बलरामपुर की कन्हर नदी पर खुटपाली व्यपवर्तन योजना के कार्यों के लिए 147 करोड़ 48 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों को 1975 हेक्टेयर खरीफ एवं 1720 हेक्टेयर रबी सहित कुल 3695 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के कार्यों को करने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने वित्त मंत्री से की शिकायत

रायपुर में आईपीएल मैच के दौरान दर्शकों से ओवरचार्जिंग का आरोप

रायपुर। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैच के दौरान दर्शकों से कथित तौर पर भारी ओवरचार्जिंग और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी (सीएसएस) ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

संस्था के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने आरोप लगाया है कि मैच के दौरान दर्शकों से खान-पान और जर्करी सामानों के लिए निर्धारित कीमत से कई गुना अधिक राशि वसूली गई। उनका कहना है कि यह स्थिति दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैदा की गई, क्योंकि सुरक्षा कारणों से स्टेडियम के अंदर बाहर से पानी और खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी।

शिकायत पत्र में बताया गया है कि 42 से 43 डिग्री तापमान के बीच आयोजित मैच के दौरान 20 रुपये की पानी की बोतल 100 रुपये में बेची गई। इसके अलावा 20 रुपये का समोसा और 15 रुपये की कोल्ड ड्रिंक भी 100 रुपये तक में दर्शकों को उपलब्ध कराई गई।

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने आज प्रदेश के वित्तमंत्री माननीय श्री ओ.पी. चौधरी से सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय के विकास और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए हर संभव विधियों और शासकीय सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की भविष्य की आत्मनिर्भरता को देखते हुए स्व-वित्त पोषित और स्व-संचालित प्रणाली को अपनाने का महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया।

रायपुर। युवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस कर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन धमतरी द्वारा एक दूरदर्शी पहल की गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस अभिनव प्रयास का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल स्किलिंग के क्षेत्र में निपुण बनाकर उनके लिए रोजगार के नए द्वार खोलना है।

पी.जी. कॉलेज धमतरी के आईटी भवन में आयोजित इस परीक्षा में जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कुल प्रतिभागी 166 ने हिस्सा लिया, जिसमें से ऑफलाइन माध्यम 107 विद्यार्थी और ऑनलाइन माध्यम 59 विद्यार्थी शामिल हुए। बड़ी संख्या में युवाओं की यह भागीदारी जिले में नई तकनीकों और डिजिटल साक्षरता के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।

परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को बेंगलुरु की प्रतिष्ठित संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इस विशेष प्रोग्राम में युवाओं को उन स्किल्स का



सिविल सोसायटी का आरोप है कि आरसीबी और बीसीसीआई से जुड़े वेंडरों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए दर्शकों से 500 प्रतिशत से लेकर 1000 प्रतिशत तक अधिक कीमत वसूली। संस्था ने इसे खेल के नाम पर खुली लूट करार दिया है।

डॉ. कुलदीप सोलंकी ने पत्र में यह भी दावा किया है कि स्टेडियम के अंदर अधिकांश लेनदेन केवल नकद में किए गए और किसी भी ग्राहक को आधिकारिक बिल या रसीद नहीं दी गई। संस्था के अनुसार यह मामला संभावित जीएसटी चोरी की ओर इशारा करता है।

पत्र में अनुमान जताया गया है कि मैच देखने करीब 60 हजार दर्शक पहुंचे थे और एक ही मुकाबले में लगभग 10 से 11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसमें से 8 से 9 करोड़ रुपये तक की राशि कथित तौर पर अवैध वसूली के रूप में दर्शकों से ली गई। वहीं केवल पानी की बिक्री से करीब 60 लाख रुपये वसूले जाने का अनुमान लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने राज्य सरकार से पूरे मामले को विस्तृत जांच करने की मांग की है। संस्था ने सुझाव दिया है कि जीएसटी कमिश्नर और संबंधित विभागों के अधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रकरण की सुझाव जांच कराई जाए।

इसके अलावा आगामी 13 तारीख को होने वाले आईपीएल मुकाबले में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सख्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है।

संस्था ने यह भी मांग उठाई है कि वेंडरों द्वारा कथित रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि को जुर्माने सहित रिकवर कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जाए।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए दर्शकों के हितों की रक्षा करेगी और खेल आयोजनों के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने वित्तमंत्री को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में मीडिया सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों का शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क बेहद किफायती रखा गया है। इससे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के सुदूर अंचलों के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग सहित सभी समुदायों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितकारी और कल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ निधन और कमजोर वर्ग के छात्रों को मिल रहा है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बोझ के ज्ञानार्जन कर पा रहे हैं।

व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा जिनकी वर्तमान में वैश्विक उद्योगों में सर्वाधिक मांग है। चयनित विद्यार्थियों को आगे विशेष एआई स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्था Learnijoy Bangalore द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों को AI Video Generation, Website Development, AI Agents Making, Automation Tools, Digital Productivity, Prompt Engineering तथा आधुनिक तकनीकी समाधान विकसित करने जैसी अत्याधुनिक स्किल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार, इंटरनेट, फ्रीलांसिंग और डिजिटल उद्यमिता के काबिल बनाना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में बेरोजगारी दर, विकास कार्यों, प्रधानमंत्री की अपील और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई है और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। राज्य निर्माण के बाद लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हुआ है। सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। राज्य के युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है।

कांग्रेस द्वारा मंत्रियों के गाड़ियों के काफिले कम करने की मांग पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि खर्च कम किया जाए। इस विषय पर सरकार स्तर पर विचार किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहीं संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक संकट को लेकर देशवासियों से की गई अपील पर मंत्री कश्यप ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री की बातों को

8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बने पुलिस आरक्षक

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ने सामाजिक समावेशन और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। राज्य में 8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का चयन पुलिस आरक्षक पद पर हुआ है। यह सफलता वर्ष 2024 को भर्ती प्रक्रिया तथा 2025 में आयोजित शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मिली है।

चयनित उम्मीदवारों में सुश्री भूमि मानिकपुरी, सुश्री खुशी ध्रुव, सुश्री संजना ध्रुव, सुश्री रानू यादव, सुश्री पवित्रा चंद्रवंशी, सुश्री लक्ष्मी साहू, सुश्री अस्परा जायसवाल और सुश्री सुभी यादव शामिल हैं। ये उम्मीदवार रायपुर, बेमेतरा, शारीर-चांपा और कांकेर सहित विभिन्न जिलों से हैं। सामाजिक चुनौतियों, अस्वीकार्यता और अनेक व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद इन सभी ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।

यह उपलब्धि केवल रोजगार प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय की बढ़ती भागीदारी, सम्मान और स्वीकार्यता का सशक्त संदेश भी देती है। पुलिस विभाग जैसे जिम्मेदार क्षेत्र में उनकी नियुक्ति राज्य में समान अवसर आधारित शासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी इस सफलता में समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभाग द्वारा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण, आवागमन सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में निरंतर सहयोग मिला।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह चयन एक प्रेरणादायी कदम माना जा रहा है।



छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटी: केदार कश्यप



गंभीरता से लेने की जरूरत है। आने वाले एक साल तक प्रधानमंत्री की बातों को अपनी दिनचर्या में उतारने की आवश्यकता है। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की अपील पर तंज कसने पर पलटवार करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि आरोप लगाणा कांग्रेस का दायित्व बन गया है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संकट को देखते हुए देशहित में अपील की है। कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि उस समय देश को खोखला करने का काम किया गया, जबकि आज भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है।

भाजपा द्वारा पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताए जाने के मुद्दे पर वन मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद तुष्टिकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन राष्ट्रपति को भी मंदिर जाने से रोका गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने बयानों से तुष्टिकरण की राजनीति को उजागर कर रहे हैं और इसी कारण देशभर में कांग्रेस का सफाया हो रहा है।

फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के वन मंत्री के बंगले पहुंचने पर मंत्री कश्यप ने कहा कि अभ्यर्थियों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिजिकल टेस्ट पूरा कर लिया गया है और इस विषय पर अधिकारियों से चर्चा भी हुई है। व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। दिसंबर या जनवरी तक लिखित परीक्षा कराई जा सकती है।

बैंज ने आरोप लगाया कि पहले जिन लोगों पर पेपर लीक कराने के आरोप लगते रहे, आज वही लोग सत्ता में बैठकर राज कर रहे हैं। बैंज ने कहा कि सरकार पेपर लीक करने वालों को बचाने और उपकृत करने का काम कर रही है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो आठवीं, दसवीं और बारहवीं तक के पेपर सुरक्षित नहीं हैं, उन्होंने पीएससी परीक्षा और उसकी जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां जांच होनी चाहिए, वहां भी पारदर्शिता नजर नहीं आ रही। दीपक बैंज ने कहा कि पेपर लीक देश का बड़ा घोटाला बन चुका है, लगातार हो रही घटनाओं से युवाओं का सिस्टम और सरकार पर भरोसा टूटा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की।

धमतरी में एआई क्रांति: अत्याधुनिक कौशल और एआई से सुसज्जित होंगे युवा

रायपुर। युवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस कर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन धमतरी द्वारा एक दूरदर्शी पहल की गई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस अभिनव प्रयास का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल स्किलिंग के क्षेत्र में निपुण बनाकर उनके लिए रोजगार के नए द्वार खोलना है।

पी.जी. कॉलेज धमतरी के आईटी भवन में आयोजित इस परीक्षा में जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कुल प्रतिभागी 166 ने हिस्सा लिया, जिसमें से ऑफलाइन माध्यम 107 विद्यार्थी और ऑनलाइन माध्यम 59 विद्यार्थी शामिल हुए। बड़ी संख्या में युवाओं की यह भागीदारी जिले में नई तकनीकों और डिजिटल साक्षरता के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।

परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को बेंगलुरु की प्रतिष्ठित संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। इस विशेष प्रोग्राम में युवाओं को उन स्किल्स का



व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा जिनकी वर्तमान में वैश्विक उद्योगों में सर्वाधिक मांग है। चयनित विद्यार्थियों को आगे विशेष एआई स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्था Learnijoy Bangalore द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रतिभागियों को AI Video Generation, Website Development, AI Agents Making, Automation Tools, Digital Productivity, Prompt Engineering तथा आधुनिक तकनीकी समाधान विकसित करने जैसी अत्याधुनिक स्किल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार, इंटरनेट, फ्रीलांसिंग और डिजिटल उद्यमिता के काबिल बनाना है।

प्रशिक्षण पूरी तरह से 'Industry-Oriented' होगा, जिससे युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकें।

कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने इस पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, आने वाला युग एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। हमारा प्रयास है कि धमतरी के युवाओं को समय रहते वैश्विक स्तर की स्किलिंग उपलब्ध कराई जाए। इससे वे न केवल बेहतर रोजगार प्राप्त करेंगे, बल्कि स्वयं के स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजक भी बन सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन भविष्य में भी नवाचार, स्टार्टअप प्रमोशन और टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निरंतर बढ़ावा देता रहेगा।

गौरतलब है कि इससे पहले Yuva Fest में आयोजित एआई वर्कशॉप के माध्यम से 4 विद्यार्थियों को इंटरनेट शिप का अवसर मिला था, जिससे प्रेरित होकर इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। जिला प्रशासन की यह पहल धमतरी को तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

पीएम मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील के समर्थन में उतरा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन

प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी बोले- अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, पारंपरिक स्वर्ण कारीगरों के संरक्षण के लिए स्वर्ण शिल्प कला बोर्ड गठन की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि सराफा व्यापारियों को इस मुद्दे पर चबराने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह करम दीर्घकाल में देश की अर्थव्यवस्था और सराफा व्यापार दोनों को मजबूती प्रदान कर सकता है।

कमल सोनी ने कहा कि पिछले दो वर्षों से वैश्विक युद्ध, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता और बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर सराफा कारोबार पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सामान्य आभूषण व्यापार लगभग सीमित

होकर केवल बुलियन आधारित लेन-देन तक सिमट गया है, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ा।

उन्होंने कहा कि लगातार मूल्य अस्थिरता के कारण व्यापारियों को नुकसान और कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री की यह अपील भविष्य में व्यापक आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकती है। उनके अनुसार यह समय सराफा बाजार को केवल सोना खरीदने-बेचने तक सीमित रखने के बजाय उसे सेवा क्षेत्र आधारित मॉडल में विकसित करने का है।

कमल सोनी ने कहा कि यदि सोने के आयात में कमी आती है तो इससे देश का



विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहेगा और रुपये की स्थिति मजबूत होगी। इसका अप्रत्यक्ष लाभ विभिन्न क्षेत्रों के छोटे उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा। उन्होंने इसे राष्ट्रहित में व्यापारियों की महत्वपूर्ण

भागीदारी बताया।

उन्होंने घरेलू स्तर पर निष्क्रिय पड़े सोने को 'डेड स्टॉक' बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सोच का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ाना है। यदि लोग बैंकों, उद्योगों और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएं, तो इससे रोजगार सृजन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

कमल सोनी ने उपभोक्ताओं को बड़े कॉर्पोरेट ज्वेलरी ब्रांड्स की आक्रामक मार्केटिंग से सावधान रहने की सलाह भी दी। उन्होंने दावा किया कि ऐसे व्यापार मॉडल से बड़ी मात्रा में पूंजी देश से बाहर चली जाती है, जबकि स्थानीय सराफा व्यापार और पारंपरिक कारीगरों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता।

इस दौरान उन्होंने लंबे समय से लंबित १%स्वर्ण शिल्प कला बोर्ड के गठन की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों में अभी तक ऐसा बोर्ड गठित नहीं हुआ है, वहां तत्काल इसकी स्थापना की जानी चाहिए। उनके अनुसार यह बोर्ड पारंपरिक स्वर्ण कारीगरों की कला और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही कारीगरों को सरकारी योजनाओं, रियायती ऋण, बीमा सुविधाओं और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। कमल सोनी ने कहा कि १%के इन इंडिया की अवधारणा को मजबूत करने के लिए पारंपरिक स्वर्ण शिल्प उद्योग को संरक्षण और संस्थागत समर्थन दिया जाना समय की मांग है।

हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों से कुछ महत्वपूर्ण सबक

कल्याणी शंकर

हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनावों में, 3 प्रमुख मुख्यमंत्रियों को अपत्याशित हार का सामना करना पड़ा, एक ऐसी स्थिति जिसे राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग प्रक्रिया के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से के रूप में पहचानते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री अपने चुनाव हार गए। चुनावों में जीतना और हारना राजनीति में आम बात है। हालाँकि, यह याद रखना जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवानी जैसे कुछ राजनेताओं ने लचीलापन दिखाया और दशकों की असफलताओं को सहने के बाद भी वापसी की, जो भविष्य के राजनीतिक नवीनीकरण के लिए आशा जगाता है। इन प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं की हार, जिनमें से प्रत्येक पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है- अरविन्द केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे जाने-माने व्यक्तियों द्वारा पहले झेली गई चुनौतियों के साथ मिलकर, विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक के पास मजबूत क्षेत्रीय आवाजों को कम कर देती है। यह स्थिति उन लोगों के लिए निराशाजनक हो सकती है, जो प्रतिनिधित्व के लिए इन नेताओं की ओर देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं। सबसे प्रमुख है भाजपा का विस्तार, जिसने पश्चिम बंगाल और असम में जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। यह विकास एक बढ़ते केंद्रीय प्रभाव का संकेत देता है, जो क्षेत्रीय दलों को चुनौती देता है और भारतीय राजनीति में सत्ता के समग्र संतुलन को प्रभावित करता है। क्षेत्रीय दलों के लिए बदलाव कठिन हो सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उनके समर्थकों की भावनाओं को पहचानने और उस कठिन दौर को समझने की आवश्यकता है जिससे वे गुजर रहे हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिति अधिक तीव्र हो रही है क्योंकि पार्टियां पदों के पीछे काम कर रही हैं। तमिल वलूर काची (टी.वी.के.) ने 108 सीटें जीतीं लेकिन बहुमत हासिल करने के लिए उसे 118 सीटों की जरूरत थी। उन्हें कांग्रेस, सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम) और वी.सी.के. का समर्थन प्राप्त है। जबकि कुछ क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं, विजय की टी.वी.के. का उदय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण लाता है। द्रमुक, टी.एम.सी. और सी.पी.आई. (एम) जैसे स्थापित दलों को आगे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शिवसेना आंतरिक कलह से जूझ रही है और अकाली दल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राकांपा और जद (एस) जैसे अन्य दल प्रभाव खो रहे हैं और जद (यू) पतन की ओर खि़र रहा है। इसके अतिरिक्त, बी.आर.एस. और बसपा अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो उनके समर्थकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव में जीतकर पश्चिम बंगाल में सी.पी.आई. (एम) के 33 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। हालाँकि, वह 2026 के अप्रत्याशित चुनाव परिणामों में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद निराश थीं। तो, ममता बनर्जी के लिए आगे क्या ? वह विरोध करती रहेंगी और टी.एम.सी. को एकजुट करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी, जिससे वह 'इंडिया' गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेंगी। हालाँकि, पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रभाव बढ़ने के कारण कई समर्थकों और विश्लेषकों को उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता है। यह बदलाव क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है। टी.एम.सी., द्रमुक और लेफ्ट जैसे स्थापित दलों को अपनी हालिया चुनावी विफलताओं पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यदि वे अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, तो भाजपा बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी और द्रमुक तथा अन्नद्रमुक दोनों अपना मतदाता आधार खो सकते हैं। वे जितनी जल्दी यह करेंगे, उनकी पार्टियों के लिए उतना ही अच्छा है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यज्ञ का दक्षिणा से विवाह

कहा जाता है कि---यज्ञ ने अपनी सहोदरा भगिनी दक्षिणा के साथ विवाह किया था, यह आख्यान इस प्रकार है--

पौराणिक स्वरूप

प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् । मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समायोजत् ॥३॥ यस्तयोः पुरुषः साक्षाद् विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् । या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूताऽनपायिनी ॥४॥ तो कामयानां भगवानुवाह यजुर्वा पतिः । तुष्टायां तोषमाप्नोऽजनयद् द्वादशाल्मजान् ॥६॥ (श्रीमद्भागवत ४ । 1)

अर्थात्- भगवान् प्रजापति रुचि द्वारा (मनु) की आकृति- भागम्) उस कन्या में परम समधि से ब्रह्मतेजोमय एक जोड़ा उत्पन्न हुवा ॥३॥ उन दोनों में जो पुरुष था वह यज्ञावतारधारी साक्षात् विष्णु भगवान्

थे और जो दक्षिणा नामक स्त्री थी वह अनपायिनी लक्ष्मी अंशभूत थी ॥४॥ यजुर्वेद के अधिष्ठाता भगवान् यज्ञदेव ने इस इच्छित फलदायिनी दक्षिणा के साथ विवाह किया, और संतुष्ट दक्षिणा में प्रसन्न हुवे यज्ञ से. तोष-प्रतोष आदि बारह पुत्र उत्पन्न हुवे ॥6 ॥

वैदिक स्वरूप

(क) यो वै विष्णुः स यज्ञः ।

(शतपथ 5 । 2 । ३ । ६)

(ख) पुरुषो वै यज्ञस्तस्य शिर एव हविर्धाने मुखमा-ह्वनीय उदरं सदी ।

(कौषीतकी 17 । 7)

(ग) एषा ह वै यज्ञस्य पुरोगवी यर्दक्षिणा ।

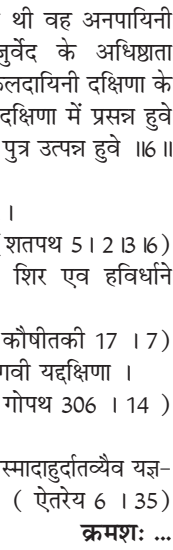
(गोपथ 30६ । 14)

दक्षिणा भवत्यल्पिकापि ।

(घ) यज्ञोऽर्दक्षिणो र्ष्यति तस्मादाहुर्दातव्यैव यज्ञ-

(ऐतरेय 6 । 35)

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

मोदी द्वारा विदेशी मुद्रा बचाने के आह्वान के निहितार्थ

कमलेश पांडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार की आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। पहले कृत्रिम वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19), फिर रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका/ इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। फिलवक्त मौजूदा वैश्विक संकट से भारत को निजात दिलाने और इससे प्रभावित हो रहे आम भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने, आयातित वस्तुओं का उपभोग मितव्ययिता पूर्वक करने और इनके मौजूद देशी विकल्प को आजमाते हुए स्थायी हल निकालने और उनपर निर्भर होने की दिशा में जनसहयोग का आह्वान करके सबको चौंका दिया है।

समझा जाता है कि अमेरिका, चीन, यूरोप और अरब के कुछ देशों के द्वारा लगातार भारत विरोधी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोई अपना इस्लामिक एजेंडा भारत पर थोपना चाहता है तो कोई भारत-रूस के भरोसेमंद सम्बन्धों में पलीता लगाना चाहता है और कोई भारत को पाकिस्तान, बंगलादेश और चीन के त्रिपक्षीय कुचक्र में उलझा कर अपना आर्थिक हित साधना चाहता है। जबकि, तेजी से आर्थिक और सैन्य उन्नति कर रहा 21वाँ सदी का भारत अब रूस-ईरान-इजरायल के सहयोग से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है।

भारत-यूरोप की बढ़ती नजदीकियों और उसको निकट भविष्य में और अधिक बल देने वाली विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अमल से चिढ़े अमेरिकी डीप स्टेट और उनके चीनी-अरबी पिढुओं ने पहले ईरान को बर्बाद करने और फिर इंडिया को उसकी तपिश में झूलसाने की जो कुचक्र रची है, अब भारत उसकी भी काट ढूँढ चुका है। इस बार भारत ने लोकल फ़ॉर वोकल और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने की जगह विदेशी मुद्रा बचाने हेतु विभिन्न सकारात्मक पहल करने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी त्रासदी से निपटने के लिए आपसे कोई सोना नहीं मांग रही है, बल्कि अगले 1 साल तक इनकी खरीदारी कम करने की बात कह रही है ताकि विदेशी मुद्रा बचे। इसी कड़ी में उन्होंने उन तमाम वस्तुओं का जिक्र बारी-बारी से किया और कहा कि इनपर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होते



हैं, इसलिए अगले 1 साल तक इनका संयमित उपभोग कीजिए। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए।

स्पष्ट है कि यह सिर्फ देशभक्ति वाला संदेश नहीं होता; बल्कि यह आर्थिक संकेत भी होता है कि सरकार को वैश्विक अनिश्चितता, महंगे आयात, या डॉलर पर दबाव की चिंता है। ऐसा इसलिए कि जब विदेशी मुद्रा पर दबाव होता है, तब देश कोशिश करता है कि रुपये पर ज्यादा दबाव न पड़े, जरूरी आयात (तेल, दवा, रक्षा) जारी रह सकें, महंगाई नियंत्रित रहे, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। उल्लेखनीय है कि भारत की विदेशी मुद्रा कई बड़े क्षेत्रों में खर्च होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च आयात पर होता है।

अगर सबसे ज्यादा की बात करें, तो आमतौर पर क्रम कुछ ऐसा रहता है: 1. कच्चा तेल ? 2. इलेक्ट्रॉनिक्स/मशीनरी ? 3. सोना ? 4. रसायन/उर्वरक ? 5. रक्षा खरीद। हाल के वर्षों में भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च कच्चे तेल के आयात पर ही रहा है। उनके हाल के बयान की बात करें तो मौजूदा वैश्विक संकट (जैसे युद्ध, तेल कीमतें, सप्लाई-चेन दबाव) के बीच प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने की बात जब कही, तो इसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि भारत डॉलर में होने वाले खर्च को कम करे और आय बढ़ाए।

उल्लेखनीय है कि ऐसे आह्वानों के मुख्य बिंदु आमतौर पर ये होते हैं- आयात कम करना/ आत्मनिर्भरता बढ़ाना- खासकर तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, खाद्य तेल जैसी चीजों में विदेश निर्भरता घटाना। लोकल खरीदें और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की बात इसी से जुड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी मुद्रा बचाने की बात का राजनीतिक-आर्थिक मतलब संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन आम तौर पर इसके कई स्तर होते हैं। इसके मायने क्या हैं ? इसे ऐसे

आशुतोष गर्ग

किसी समय पांचाल पर राजा विभ्राज का शासन था। विभ्राज की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र ब्रह्मदत्त को राजा बना दिया गया। ब्रह्मदत्त अत्यंत पराक्रमी, शास्त्रों के ज्ञाता, योगविद्या में निपुण और प्राणियों की भाषा समझते थे। उनकी पत्नी देवल कन्या संनति थी, जो स्वयं ब्रह्मवादिनी और धर्मनिष्ठ थी। दोनों मिलकर राज्य का संचालन करते थे। एक दिन ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी संनति के साथ उद्यान में विहार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक चींटा और चींटी परस्पर विवाद कर रहे थे। ब्रह्मदत्त उनकी बातचीत ध्यान से सुनने लगे।

काम-विह्वल चींटा अपनी पत्नी से गिड़गिड़ाकर कह रहा था, ‘प्रिये! तुम इस संसार में सबसे सुंदर हो। तुम्हारी चाल,

समझते हैं।

पहला, आर्थिक मायने: आयात बिल कम करने का संकेत। चूंकि भारत का बड़ा विदेशी मुद्रा खर्च तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर होता है। लिहाजा जब सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की बात करती है, तो अक्सर मतलब होता है- घरेलू उत्पादन बढ़ाओ (मेक इन इंडिया जैसी नीति), आयातित वस्तुओं पर निर्भरता घटाओ, ऊर्जा बचत या वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दो और रुपये और व्यापार घाटे पर दबाव कम करो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो रुपये पर दबाव पड़ सकता है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है।

इसलिए विदेशी मुद्रा बचाने का संदेश बाजार को यह संकेत भी देता है कि सरकार बाहरी आर्थिक जोखिमों को लेकर सतर्क है। चूंकि ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा अहम है इसलिए तेल आयात महंगा होने पर सरकार कभी-कभी ईंधन बचत, एथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहन, या घरेलू उत्पादन पर जोर देती है ताकि डॉलर खर्च कम हो। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने से आयात भुगतान, संकट प्रबंधन और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है।

दूसरा, राजनीतिक मायने: आत्मनिर्भरता की राजनीतिक कथा जैसा संदेश अक्सर देशी बनाम विदेशी निर्भरता या आत्मनिर्भरता के नैरेटिव से जुड़ता है—यानी आर्थिक राष्ट्रवाद का तत्व। वहीं जनता से व्यवहार परिवर्तन की अपील के पीछे कभी-कभी सरकार जनता से कुछ आदतें बदलने (जैसे ऊर्जा बचत, आयातित वस्तुओं का कम उपभोग) की नैतिक अपील करती है, ताकि नीति को सामाजिक समर्थन मिले। इससे कठिन आर्थिक समय का संकेत भी मिलता है।

स्पष्ट है कि यदि बयान ऐसे समय आए जब तेल महंगा हो, डॉलर मजबूत हो, या वैश्विक संकट हो, तो यह आर्थिक सावधानी का संकेत भी माना जा सकता है—हालाँकि जरूरी नहीं कि संकट ही हो। जहां तक नीतिगत फैसलों की पृष्ठभूमि तैयार करने की बात है तो ऐसे बयान आगे चलकर कुछ कदमों (आयात शुल्क, उत्पादन प्रोत्साहन, ऊर्जा नीति, निर्यात बढ़ावा) के लिए राजनीतिक आधार भी बना सकते हैं।

आइए, यहां पर समझते हैं कि किन-किन वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होती है—

पहला, कच्चा तेल और पेट्रोलियम आयात:

राजा ब्रह्मदत्त को ऐसे मिला मोक्ष



वाणी और रूप सब अद्भुत हैं। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, फिर किस कारण मुझसे रुठ हो गई हो?’ क्रोधित चींटी ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, ‘धूर्त! व्यर्थ की मोटी बातें मत करो। कल ही तुमने मेरा तिरस्कार करके लड्डु का चूर्ण दूसरी चींटी को दिया था। क्या यह सत्य नहीं है?’ चींटा लज्जित होकर बोला, ‘प्रिये! वह मेरी भूल थी। तुम्हारे समान रूप देखकर मैं भ्रमित हो गया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूं, मुझे क्षमा कर दो।’ उसकी विमम्रता और पश्चात्ताप देखकर चींटी का क्रोध शांत हो गया और वह प्रसन्न हो गई। यह दृश्य देखकर ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। रानी ने पूछा, ‘राजन! अचानक आप क्यों हंसे ? इसका कारण क्या है?’

राजा ने सारी बात रानी को बता दी, परंतु रानी को विश्वास नहीं हुआ। रानी ने कहा, ‘यदि आप सत्य नहीं बताएंगे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।’ रानी के कठोर वचनों से राजा मौन हो गए। वह सत्य जानते हुए भी उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए भगवान श्रीहरि की आराधना करने का निश्चय किया। वह सात दिनों तक ध्यान में लीन रहे। सातवाँ रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, ‘राजन! प्रातःकाल एक वृद्ध ब्राह्मण तुम्हें इस घटना का रहस्य बताएगा।’

अगले दिन राजा अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकले। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को यह कहते

सुना, ‘जो पहले कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण, दाशपुर में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग और मानसरोवर में चक्रवाक पक्षी के रूप में जन्मे थे, वही अब यहां ब्रह्मदत्त के रूप में निवास कर रहे हैं।’ यह वचन सुनते ही राजा भूमि पर गिर पड़े। उन्हें अपने पूर्वजन्मों का स्मरण हो गया। उन्होंने देखा कि वह अनेक जन्मों से कर्मों के बंधन में बंधे हुए थे और पितरों के रुठ हो जाने से पतित हो गए थे। इसके बाद राजा ब्रह्मदत्त ने श्राद्ध और पितृर्भक्ति का महत्व समझा। उन्होंने उस ब्राह्मण को कई गांव और धन दान में दिया। फिर अपने पुत्र विष्णुक्सेन को राज्य सौंप दिया और वैराग्य धारण कर वन चले गए। कठोर साधना के प्रभाव से उन्होंने अंततः ब्रह्मरंभ्र के मार्ग से प्राण त्याग दिए और परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गए।

आज का इतिहास

- 1880 न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में थॉमस एडीसन ने अपना पहला विद्युत रेल का प्रदर्शन किया।
- 1888 ब्राजील के साम्राज्य की राजकुमारी इसाबेल ने लेई ऑरिंटो कानून पर हस्ताक्षर किए, औपचारिक रूप से ब्राजील में दासता को समाप्त कर दिया।
- 1899 एसपोर्ट्स क्लब विटोरिया एसोसिएशन फुटबॉल क्लब साल्वाडोर ब्राजील में स्थापित किया गया।
- 1907 रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की 5वाँ बैठक लंदन के गुप्त में आयोजित की गई।
- 1913 रूसी अमेरिकी इगोर सिकोरस्की ने दुनिया का पहला मल्टी-इंजन फिक्स्ड-विंग विमान, रस्की वाइटज़ को उड़ाया, जिसे उन्होंने डिज़ाइन किया था।
- 1930 ब्रिटिश श्रम मंत्रालय 1.7 मिलियन बेरोजगारो की लिस्ट बनायीं।
- 1931 पॉल ड्यूमर सफल द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए।
- 1935 लंदन की हॉरर फिल्म वेयरवोल्फ जारी की गई।
- 1948 किबुत्ज़ केफ़र एट्रिज़्यन के पंद्रह यहूदी निवासी अरब लीज़नैड अरब वासियों के साथ दो दिन की लड़ाई के बाद अपने आत्मसमर्पण कर रहे थे।
- 1950 एफ़आईए फ़ॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप की पहली दौड़ इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन में आयोजित की गयी।
- 1981 मेहमत अली अगाका ने वेटिकन सिटी के पोप जॉन पॉल द्वितीय सेंट पीटर स्क्वायर में गंभीर रूप से गोली मारकर घायल कर दिया।
- 1985 अमेरिकी ब्लैक लिबरेशन ग्रुप के ग्यारह सदस्यों को मोवे को तब मारा गया जब एक फ़िलाडेल्फिया पुलिस हेलीकॉप्टर ने एक छापे के दौरान उनके घर पर बम गिराया।
- 1992 ली होंगज़ी ने फाल्तुन गोंग को चीन के ज़िलिन प्रांत के चांगचुन में एक सार्वजनिक व्याख्यान में पेश किया।
- 1996 गंभीर तूफान और एक बवंडर ने बांग्लादेश में 600 लोगों को मार डाला।
- 1999 कार्लो एज़ेज़ो सिमाई इटली के राष्ट्रपति चुने गए।

2000 एनस्किडे, नीदरलैंड में एक आतिशबाजी कारखाने में विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 22 मौतें हुईं और लगभग 450 मिलियन डॉलर की क्षति हुई।

2001 सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने आम चुनाव जीता, दूसरी बार के लिए इटली के प्रधानमंत्री बने।

2014 तुर्की की एक खदान में विस्फोट होने और आग लगने से 238 खदान कर्मियों की मौत।

75 वर्षों में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना सोमनाथ

सौरभ वार्धन्य

भारत की सांस्कृतिक आत्मा और आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होना केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की ऐतिहासिक चेतना, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी महत्वपूर्ण क्षण है। आज जब देश इस गौरवपूर्ण यात्रा को स्मरण कर रहा है, तब यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि केंद्र की भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की अदम्य शक्ति और सनातन परंपरा की अमर गाथा है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत के संघर्ष, आक्रमणों और पुनर्जागरण की कहानी कहता है। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई बार ध्वस्त किए जाने के बाद भी यह मंदिर भारतीय आस्था का केंद्र बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौहपुरुष सरदार पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। वर्ष 1951 में

तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसने स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान को नई पहचान दी। इन 75 वर्षों में सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक बन गया। विशेष रूप से पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को जिस प्रकार गति दी है, वह उल्लेखनीय है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, अयोध्या में राम मंदिर और केदारनाथ पुनर्विकास जैसे अनेक प्रकल्प इस सोच को मजबूत करते हैं कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर ही विश्व में नई पहचान बना सकता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर यहां अपने श्राप से मुक्ति पाई थी, इसी कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा। अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन काल से श्रद्धा और व्यापार दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार इसका उल्लेख



अनेक प्राचीन ग्रंथों और यात्रावृत्तों में मिलता है।

सोमनाथ का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही संघर्षपूर्ण भी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने इस मंदिर पर आक्रमण कर इसकी अपार संपदा लूटी और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भी विभिन्न कालखंडों में कई विदेशी आक्रांताओं ने इसे निशाना बनाया। लेकिन हर विनाश के बाद भारतीय समाज ने इसे फिर से खड़ा किया। यही तथ्य दर्शाता है कि किसी राष्ट्र की आत्मा को केवल पत्थरों

को तोड़कर समाप्त नहीं किया जा सकता। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आधुनिक सुविधाओं और भव्य स्थापत्य ने इसकी गरिमा को और बढ़ाया है। साथ ही यह मंदिर भारत को यह स्मरण कराता है कि हमारी संस्कृति ने हर संकट के बाद स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता दिखाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई बार यह कहा है कि विकास और विरासत साथ-साथ चल सकते हैं। यही कारण है कि सरकार ने एक ओर आधुनिक आधारभूत संरचना पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर प्राचीन मंदिरों, तीर्थों और सांस्कृतिक केंद्रों के संरक्षण को भी महत्व दिया। सोमनाथ मंदिर परिसर का आधुनिकीकरण, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और आसपास के क्षेत्र का विकास इसी दृष्टि का हिस्सा है। हालांकि, इस अवसर पर यह भी

आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित न रह जाए। मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के साथ-साथ देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर भी समान गंभीरता से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय गौरव तभी सार्थक होगा, जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भारत की उस अटूट चेतना का प्रमाण हैं, जिसने सदियों के संघर्ष के बाद भी अपनी पहचान को जीवित रखा। यह अवसर केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की सांस्कृतिक दिशा तय करने का भी है। यदि विरासत और विकास का संतुलन बना रहा, तो भारत विश्व मंच पर अपनी सभ्यतागत शक्ति के रूप में और अधिक मजबूती से उभरेगा।

आज जब भारत विश्व मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है, तब सोमनाथ जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र देश की सांस्कृतिक शक्ति को मजबूत करते हैं। पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक

अध्ययन के क्षेत्र में भी ऐसे तीर्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी धरोहरों के संरक्षण, स्वच्छता और ऐतिहासिक महत्व को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य गंभीरता से करें।

सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना और आत्मविश्वास में निहित होती है। समय बदलता है, चुनौतियाँ बदलती हैं, लेकिन जो सभ्यता अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है, वह सदैव मजबूत बनी रहती है। सोमनाथ इसी अमर भारतीय चेतना का प्रतीक है। वर्तमान समय में जब इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को लेकर नई बहसें चल रही हैं, तब सोमनाथ का इतिहास हमें संतुलित दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देता है। यह मंदिर प्रतिशोध का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देता है। भारत की शक्ति उसकी विविधता और सांस्कृतिक निरंतरता में निहित है, और सोमनाथ उसी निरंतरता का जीवंत प्रतीक है।

बंगाल विजय ने दिया भाजपा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक निर्णायक अवसर

नीलेश वर्मा

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत की पूर्वी सीमाओं से जुड़े उन गंभीर प्रश्नों पर निर्णायक कार्रवाई का ऐतिहासिक अवसर बनकर सामने आया है, जिनसे देश दशकों से जूझ रहा है। बांग्लादेश सीमा के रास्ते होने वाली अवैध घुसपैठ, तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क और बदलते जनसंख्या संतुलन ने पूर्वोत्तर भारत से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक गहरी चिंता पैदा की है। आज केंद्र और पूर्वी भारत में राष्ट्रवादी सोच को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है, तब देश की अपेक्षा है कि सीमाओं की सुरक्षा, सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कठोर एवं ऐतिहासिक कदम उठाए जाएँ। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में ही उसके प्रभाव या सहयोगी दलों की सरकारें मौजूद हैं। तो यह प्रश्न अधिक प्रासंगिक हो गया है कि क्या अब इस चुनौती पर निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है? हाल के राजनीतिक परिवर्तनों और बंगाल में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक शक्ति को देखे की जनता एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। क्योकि पश्चिम बंगाल भारत-बांग्लादेश सीमा का सबसे संवेदनशील द्वार माना जाता है। यदि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मजबूत होता है, तो सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ पर रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अधिक प्रभावी रणनीति लागू की जा सकती है। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा विश्व की सबसे जटिल सीमाओं में से एक पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से गुजरने वाली यह सीमा अनेक स्थानों पर नदियों, जंगलों और घनी आबादी से होकर निकलती है। यही कारण है कि दशकों से यह क्षेत्र अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों के लिए चुनौती बना

हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने समय-समय पर जनसंख्या परिवर्तन, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और स्थानीय पहचान पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र रहा है। स्थानीय समुदायों में यह आशंका समय-समय पर सामने आती रही है कि अनियंत्रित प्रवास उनकी सांस्कृतिक पहचान, भूमि, रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे विषय देश की राजनीति के केंद्र रहे हैं। इन अधिनियमों के द्वारा वास्तविक नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकेगा। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास वह राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय दिखाई देता है, जिसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है। केंद्र सरकार, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राज्य प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सीमा प्रबंधन को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में अब तक फेंसिंग अधूरी है, वहाँ कार्य में तेजी लाई जा सकती है। ड्रोन निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल कैमरे, सेंसर आधारित तकनीक और आधुनिक खुफिया तंत्र जैसी व्यवस्थाएँ सीमा सुरक्षा को नई मजबूती दे सकती हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और पूर्वोत्तर राज्यों में अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियाँ इस अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं। अब देश की निगाह इस बात पर टिकी है कि यह अवसर केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित रहेगा या वास्तव में घुसपैठ पर नियंत्रण, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।

भारत और मोदी के बारे में वाशिंगटन पोस्ट की बदली धारणा

नीरज कुमार दुबे

अमेरिका का प्रमुख समाचार-पत्र वाशिंगटन पोस्ट वैसे तो अक्सर भारत विरोधी लेख ही प्रकाशित करता है लेकिन अब उसने एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत के बारे में सकारात्मक लेख प्रकाशित किया है। इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण ने भारत की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती ताकत को लेकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लंबे समय से पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से जुड़े विश्लेषकों और भारत के विपक्षी दलों का मानना रहा कि भारत जैसी अत्यंत विविधभाषी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मजबूत नेतृत्व वाली राजनीति की सीमाएं होंगी और अंततः ऐसी राजनीति का प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस धारणा को गहरी चुनौती दी है।

विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को इस विश्लेषण में ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा गया है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विशिष्टता और मजबूत स्थानीय राजनीतिक परंपराओं वाला राज्य माना जाता रहा है। यहां की राजनीति पर लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा और माना जाता था कि उत्तर भारत केंद्रित तथा हिंदी भाषी छवि वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां गहरी पैठ बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन हालिया चुनावी परिणामों ने इस सोच को बदल दिया।

विश्लेषकों में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के सामने मजबूत दीवार माना जाता था। यह धारणा भी मजबूत थी कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता किसी एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वस्वीकार्य बनने से रोकेगी। किंतु पश्चिम बंगाल में मिली सफलता ने यह संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब उन क्षेत्रीय और सांस्कृतिक बाधाओं को भी पार कर रही है जिन्हें और उसके विस्तार की सीमा माना जाता था।

लेख में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को भी असाधारण बताया गया है। पार्टी की सरसंख्ये का दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल से अधिक बताया गया है। विश्लेषण के अनुसार पार्टी के लगभग चौदह करोड़ सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी अधिक हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री



नरेंद्र मोदी को मानव इतिहास में सबसे अधिक जनसमर्थन पाने वाले नेताओं में गिना गया है। विभिन्न वैश्विक सर्वेक्षणों में भी उनकी लोकप्रियता लंबे समय से शीर्ष पर बनी हुई है।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान अब केवल भारत के लोकप्रिय नेता तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह वैश्विक राजनीति में भी एक प्रभावशाली और निर्णायक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। दुनिया के अनेक देशों में भारत की बढ़ती साख के पीछे मोदी की सक्रिय कुटनीति, मजबूत निर्णय क्षमता और वैश्विक मंचों पर भारत की स्पष्ट उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि ऐसे समय में जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े वैश्विक नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों और जनमत अध्ययनों में मोदी लंबे समय से दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत का नेतृत्व अब केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भी उसकी निर्णायक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में आलोचनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद पश्चिम का निष्कर्ष यह है कि केवल चुनावी प्रबंधन या संस्थागत प्रभाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सफलता को नहीं समझा जा सकता। पार्टी ने कुछ दशकों के भीतर सीमित प्रभाव वाले संगठन से देश के 21 राज्यों में सत्ता तक का सफर तय किया है। इसके विपरीत

स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी अब कुछ गिने चुने राज्यों तक सीमित होती दिखाई दे रही है।

लेख में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच संगठनात्मक अंतर को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। कांग्रेस को जहां स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और अभिजात वर्ग का समर्थन मिला, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर लंबे संगठनात्मक संघर्ष के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की। पार्टी ने जाति, भाषा, क्षेत्र और धार्मिक परंपराओं से परे व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार किया।

इस पूरे विस्तार के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। सौ वर्ष पुराने इस संगठन ने लाखों कार्यकर्ताओं और अनेक सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यापक वैचारिक ढांचा तैयार किया। विश्लेषण में कहा गया है कि श्रमिक संगठन, निजी विद्यालय नेटवर्क, छात्र संगठन और धार्मिक नेतृत्व से जुड़े अनेक मंचों के जरिये यह विचारधारा समाज के विभिन्न हिस्सों तक पहुंची। इसी मजबूत सामाजिक नेटवर्क, रणनीतिक गठबंधनों और संगठनात्मक अनुशासन ने भारतीय जनता पार्टी के उभार की मजबूत नींव तैयार की।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी भारत की बढ़ती शक्ति को इस राजनीतिक विस्तार से जोड़ा गया है। लेख में भारत को दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और तेजी से उभरती आर्थिक ताकत बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि एशिया में चीन के प्रभाव का संतुलन बनाने की क्षमता यदि किसी देश में है तो वह भारत है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का लगातार विस्तार यह संकेत देता है कि आने वाले दशकों में भारत की दिशा और एशिया की शक्ति संरचना पर इस राजनीतिक विचारधारा का गहरा प्रभाव रह सकता है।

विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक जिस राजनीतिक गिरावट की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह फिलहाल दिखाई नहीं देती। इसके उलट वर्तमान राजनीतिक संकेत यह बताते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति, उसकी वैश्विक भूमिका और एशिया का सामरिक संतुलन काफी हद तक इसी नेतृत्व और इसी राजनीतिक धारा के प्रभाव में आकार ले सकता है।

राज कुमार सिंह

भाजपा उस राजनीतिक विमर्श को भी ध्वस्त कर रही है कि उसे चुनौती देने का जो काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं कर पा रही, वह क्षेत्रीय दल बखूबी कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत और कांग्रेस के 44 सीटों पर सिमट जाने से वह विमर्श शुरू हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने भी उसे बल प्रदान किया लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से वह कमजोर पड़ने लगा है। बेशक 2024 में भाजपा को मात्र 240 सीटों पर रोक देने में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु में द्रमुक और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उसमें अहम भूमिका निभाई। बेशक कांग्रेस की सीटें भी 52 से बढ़ कर 99 हो गईं लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह क्षेत्रीय दलों के सहारे ‘परजोवी’ है। बात गलत भी नहीं थी, इन राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के सहारे ही चुनाव लड़ने को मजबूर है।

बेशक हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हैं, पर पहले दोनों राज्य लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। शायद इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा के निशाने पर क्षेत्रीय दल और उनकी सरकारें ज्यादा नजर आती हैं। कांग्रेस के अधोषिठ नेतृत्व वाला विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन स्वाभाविक ही भाजपा के 240 सीटों पर सिमट जाने को अपनी सफलता मान रहा था लेकिन उसके बाद से उसके हिस्से हार के झटके ही ज्यादा आए हैं। सिर्फ झारखंड और जम्मू-कश्मीर ही अपवाद रहे, जहां कांग्रेस की उपस्थिति का सत्ता राजनीति में ज्यादा अर्थ नहीं है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस का ही दबदबा है तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का और विधानसभा चुनाव के बाद दोनों की ही कांग्रेस से दूरियां बढ़ती दिख रही हैं।

48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीत गया। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतीं तो उद्धव की शिवसेना ने 9, जबकि शरद पवार की राकांपा



ने 8। तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन 39 में 35 सीटें जीतने में सफल रहा। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को 12 सीटों पर समेटते हुए 42 में से 29 लोकसभा सीटें जीत लीं। अलग लड़की कांग्रेस भी एक सीट जीत गई। 20 सीटों वाले केरलम् में भी कांग्रेस नीत यू.डी.एफ. 18 सीटें जीत गया, जबकि तत्कालीन सत्तारूढ़ एल.डी.एफ. के हिस्से 1 ही सीट आई। भाजपा भी पहली बार अपना खाता खोलने में सफल रही। बेशक यू.डी.एफ. की 18 में से 14 सीटें कांग्रेस की रहीं लेकिन केरलम् में गठबंधन राजनीति एक अनिवार्यता रही है। इसलिए कांग्रेस की सीटें बढ़ कर 99 हो जाने के बावजूद भाजपा के तेज रफ्तार विस्तार पर नियंत्रण में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका है। बेशक चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड, जयंत चौधरी का राश्ट्रिय लोकदल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, स्वर्गीय अजित पवार की राकांपा के अलावा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक, भाजपागीत राजग में शामिल हैं लेकिन नवीन पटनायक का बीजू जनता दल, हेमंत सोरेन का झामुमो, लालू-तेजस्वी का राजद, अखिलेश यादव की सपा, एम.के. स्टालिन का द्रमुक, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस, अरविंद केजरीवाल की ‘आप’ और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम बड़े क्षेत्रीय दल उससे दूरी बनाए हुए हैं।

संयोग कहेें या प्रयोग, 2024 से ही इन दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पटनायक के बीजद की दशकों पुरानी सत्ता ओडिशा में तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव के

साथ हुए विधानसभा चुनाव में ही उखाड़ फेंकी थी, महाराष्ट्र में चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पासा पलट दिया, जब विपक्ष हाशिए पर चला गया। भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह चमके केजरीवाल की ‘आप’ से भी भाजपा ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता छीन ली। पिछले साल के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ही ऐसे ही एकतरफा परिणाम आए, जिनके लिए विपक्ष सीधे-सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवालिया निशान लगा रहा है। अरसे से ई.वी.एम. पर संदेह जताता रहा विपक्ष अब एस.आई.आर. प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को भाजपा की अप्रत्यक्ष चुनावी मदद करार दे रहा है। बेशक चुनाव आयोग की भूमिका से जुड़े विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं लेकिन चुनाव परिणाम नहीं बदल रहे। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी का सत्ता दुर्ग अभेद्य माना जा रहा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 पार का नारा दे कर 77 सीटों पर थम गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को और बड़ा झटका दिया था। उसके चलते माना जा रहा था कि इस बार भाजपा 100 पार भले चली जाए, पर ममता की सत्ता नहीं छिगेगी लेकिन 2021 के चुनाव परिणाम 2026 में लगभग पलट गए।

बेशक तमिलनाडु की परंपरागत द्रविड़ राजनीति के विरुद्ध त्रिंशकू विधानसभा में चमत्कारिक रूप से सबसे बड़े दल के रूप में उभरी अभिनेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर की टी.वी.के. भी एक क्षेत्रीय दल ही है लेकिन दशकों पुराने स्थापित क्षेत्रीय दलों-द्रमुक और अन्नाद्रमुक तो सत्ता के खेल से बाहर नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पंजाब में ‘आप’ ही 2 ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, जिन्हें चुनावी पटखनी देना भाजपा के लिए शेष है। इन दोनों राज्यों में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब में अगर शिरोमणि अकाली और भाजपा फिर से दोस्त बन गए तो पंजाब की चुनावी तस्वीर बदलते भी देर नहीं लगेगी। हां, यह बात अलग है कि एक और क्षेत्रीय दल के रूप में शिरोमणि अकाली दल की सत्ता राजनीति में वापसी हो जाएगी लेकिन वह भाजपा का दोस्त ही होगा- जैसे कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पुडुचेरी में एन. रंगासामी आदि हैं।

10 काम जो सबसे पहले करना चाहेगी

बंगाल की शुभेंदु सरकार

सत्येंद्र प्रताप सिंह

ममता बनर्जी अपनी पराजय के लिए भले ही एसआईआर को वजह बता रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्ता विरोधी लहर थी। पराजय के बाद टीएमसी के नेता ही अब विफलताओं व कमियों को गिना रहे हैं। भाजपा भी इन विफलताओं व कमियों को भांपते हुए 10 कार्य जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जितना जल्द हो सके करना चाहेगी।

भाजपा के शीर्ष नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी के हर भाषण में घुसपैठ और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था। ऐसे में घुसपैठियों को रोकने के लिये और भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देना पहली प्राथमिकता होगी। कानून व्यवस्था को भी मजबूत व विश्वसनीय बनाना प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता के आधार पर 10 कार्यों पर एक नजर डालते हैं।

01. बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों पर रोक लगाना शुरू से ही भाजपा का एजेंडा रहा है। ऐसे में शुभेंदु सरकार पहला काम इसी मुद्दे पर करेगी। इसके लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी मजबूत की जाएगी। घुसपैठियों को पहचान कर वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शह देने वाले वालों पर सख्ती की जाएगी।

02. ममता बनर्जी के शासन में हुए भ्रष्टाचार, कट मनी, सिंडिकेट राज आदि को उजागर करने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएंगे। साथ ही कट मनी संस्कृति को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

03. राजनीतिक हिंसा को पूरी तरह समाप्त करना और पुलिस प्रशासन को दलीय राजनीति से मुक्त कर भयमुक्त व निष्पक्ष बनाना। राजनीतिक प्रतिशोध में मामलों पर रोक लगाना ताकि पुलिस प्रशासन पर आम जनता का विश्वास लौट सके।

04. संदेशखाली और आरजीकर सरीखा कांड भविष्य में न हो इसके लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना। लखी भंडार की जगह अन्र्पूर्णा भंडार लागू करना। इस योजना के तहत हर महीने 1 से 5 तारीख के मध्य 3 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33व अरक्षण भी दिया जाएगा।

05. बेरोजगार युवाओं को 3 हजार रुपये का बेरोजगारी

भत्ता देना। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को 15 हजार रुपये का फंड मिलेगा। वहीं भर्ती घोटालों से प्रभावित युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और एक करोड़ नौकरियां देने के लक्ष्य पर भी काम होगा।

06. औद्योगिकरण और रोजगार के लिए राज्य में बंद पड़े कल कारखानों को चालू कराना, नई इंडस्ट्री लाना और रोजगार के रास्ते खोलना प्राथमिकता होगी। सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को तेजी से भरना और पारदर्शिता लाना।

07. स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण और सरकारी अस्पतालों में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त करना। राज्य सरकार के स्वास्थ्य साथी कार्ड पर विचार और आयुष्मान भारत कार्ड पर निर्णय लेना।

08. इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कें बनाना और मुख्य सड़कों से जोड़ना। पुरलिया, मालदा, बालुगछाट जैसे हवाई अड्डों का परिचालन जितना जल्द हो सके सुनिश्चित करना। उत्तर बंगाल के विकास में रफ्तार लाना। खासकर, दार्जिलिंग हिल्स में गोरखा समुदाय की मांगों का स्थायी समाधान करना और उत्तर बंगाल में चार नए शहर विकसित करना।

09. डबल इंजिन सरकार आने के बाद किसानों को केंद्र का समर्थन दिलाना। कृषक बंधु योजना के अलावा पीएम-किसान सम्मान निधि जैसी केंद्रीय योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करना। जूट उद्योग को विशेष प्राथमिकता देना।

10. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लंबित 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ और भयमुक्त कामकाजी माहौल देना। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सत्ता संभालते ही 45 दिनों के अंदर राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों पेंशनभोगियों की तनखाह बढ़ाई जाएगी और उन्हें महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

बहरहाल, प्राथमिकता के 10 कार्यों में शुभेंदु सरकार को नजर कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और औद्योगीकरण पर रहने की उम्मीद है। खजाना खाली है लेकिन डबल इंजन सरकार बनने के बाद राय सरकार, केंद्र सरकार से उम्मीद तो कर ही सकती है।

सुबह उठते ही होने लगता है सिरदर्द, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं?



क्या आपको भी सुबह उठते ही सिर में तेज दर्द होता है, सिर फटने को होता है? अगर हां तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें, सुबह होने वाला सिरदर्द कई बार गंभीर समस्याओं का अलर्ट भी हो सकता है।

नींद की गड़बड़ी, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं में सुबह के समय सिर में दर्द होते रहना आम है। हालांकि कुछ मामलों में ये ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थितियों का भी संकेत हो सकता है। सुबह के समय ब्लड प्रेशर और हार्मोन लेवल में बदलाव होता है, जिससे कुछ लोगों में सिरदर्द ट्रिगर हो सकता है। वहीं कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भी सुबह सिरदर्द ज्यादा महसूस होता है।

अब सवाल ये है कि कैसे जानें कि सुबह होने वाला सिरदर्द कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है?

ब्रेन ट्यूमर के कारण सिरदर्द

हर बार सुबह होने वाला सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता।

ब्रेन ट्यूमर के मामलों में सुबह का सिरदर्द अक्सर तेज होता है और लगातार बढ़ता जाता है।

इसमें सामान्य पेनकिलर से राहत नहीं भी मिलती।

इसके साथ मतली, नजर में

बदलाव या भ्रम जैसे अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर सिरदर्द के साथ बोलने में दिक्कत, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी, याददाश्त कमजोर होने, बार-बार उल्टी या बेहोशी जैसे संकेत दिखें तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। हालांकि कभी-कभी सुबह के समय होने वाले सिरदर्द को ट्यूमर का संकेत नहीं माना जाता है। ये कई बार अन्य लाइफस्टाइल की समस्याओं का लक्षण हो सकता है।

आपको स्लीप एपनिया की दिक्कत तो नहीं?

स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय सांस बार-बार रुकती है। इससे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और सुबह उठते ही सिरदर्द हो सकता है।

डॉक्टर कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले लोगों में सुबह सिरदर्द की समस्या काफी आम है। रातभर ऑक्सीजन का स्तर कम होने से दिमाग की रक्त वाहिकाओं पर असर पड़ता है, जिससे सुबह सिर भारी लग सकता है। मोटापा, धूम्रपान, शराब और गर्दन के आसपास ज्यादा फैट होने से इसका जोखिम बढ़ जाता है।

लंबे समय तक स्लीप एपनिया

रहने पर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा हो सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है कारण

सुबह के समय होने वाला सिरदर्द कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है।

जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, उनमें तेज सिरदर्द की समस्या अधिक देखी जाती है।

अनियंत्रित ब्लड प्रेशर के कारण दिमाग की रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ता है।

हाई ब्लड प्रेशर से होने वाला सिरदर्द अक्सर सिर के पीछे महसूस होता है।

कुछ लोगों में चक्कर, धुंधला दिखना और बेचैनी भी हो सकती है। यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है।

डिहाइड्रेशन-तनाव के कारण सिरदर्द

पानी कम पीना और ज्यादा तनाव लेना भी सुबह सिरदर्द के खतरे को बढ़ाने वाला माना जाता है।

रातभर शरीर कई घंटों तक बिना पानी के रहता है, जिससे सुबह डिहाइड्रेशन हो सकता है। इससे कई लोगों को सिर में दर्द महसूस हो सकता है।

वहीं तनाव की स्थिति में शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण भी सिरदर्द पैदा हो सकता है। जिन लोगों की नींद तनाव के कारण बार-बार टूटती है, उनमें सुबह सिरदर्द की शिकायत ज्यादा देखी जाती है।

कैफीन वाली चीजों के ज्यादा सेवन, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल और अनियमित दिनचर्या के कारण भी सिरदर्द की दिक्कत हो सकती है।

सुबह का नाश्ता करने के बाद क्यों कम हो जाता है शुगर लेवल ?



सुबह का नाश्ता सबसे जरूरी होता है, ये हमारी दिन की सबसे

अहम मील मानी जाती है, हम में से कई लोग सुबह नाश्ते में हेल्दी चीजों का सेवन करते हैं. हालांकि कई लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें नाश्ते के बाद 1-4 घंटे में चक्कर आने, कमजोरी लगने, पसीना आने, भूख लगने, हाथ कांपना या घबराहट जैसी महसूस होती है, जबकि दोपहर या रात के खाने के बाद ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं.

हम में से कई लोगों तो ये शिकायत होती है, जिसे मेडिकल की भाषा में रिप्लेक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, इस समस्या में खाने के बाद Blood Sugar लेवल पहले तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है.

वया है इसके पीछे का कारण- लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? ये समस्या ज्यादातर अधिक इंसुलिन रिलीज के कारण होती है. हम में से अधिकतर लोग ब्रेकफास्ट में हाई कार्ब चीजें खाते हैं, जैसे, चाय बिस्किट, परांठा, आलू की सब्जी, ब्रेड-जैम, पोहा, उपमा, मीठा दही-फल, जूस या चावल-आलू आदि ये सभी चीजें ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाने का काम करती हैं, इससे शरीर ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है, जो बाद में शुगर लेवल को लो

कर देता है. कुछ लोगों में पैक्रियास पहले चरण में सही इंसुलिन नहीं छोड़ पाता, फिर देर से बहुत ज्यादा छोड़ता है, इससे ओवर करेक्शन होता है और शुगर गिर जाता है.

ये भी हो सकता है कारण-

शरीर रातभर कुछ नहीं इनटेक करता है, जिससे सुबह ब्लड शुगर पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. आपका ब्रेकफास्ट अगर रिफाईंड कार्ब्स से भरपूर हो तो रिप्लेशन ज्यादा तेज होता है. दोपहर और रात में ये समस्या इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि इस दौरान पिछले भोजन का असर रहता है, इसलिए उतना प्रभाव नहीं पड़ता.

अन्य संभावित कारण-

इसके पीछे कुछ और पहलू भी हो सकते हैं, जैसे प्रो-इंफ्लेमेट्री गैस्ट्रिक बायपास या पेट की सर्जरी का इतिहास

कुछ दवाइयां, अल्कोहल, या दुर्लभ मेटाबोलिक समस्याएं बहुत ज्यादा व्यायाम या अनियमित खान-पान

इस बात पर ध्यान दें कि ये शिकायत हेल्दी लोगों को भी हो सकती है, लेकिन बार-बार शिकायत होने पर डॉक्टर से जांच जरूर कराएं.

ये लक्षण दिखने पर सतर्क हो जाएं-

अगर आमतौर पर नाश्ते के 2-4 घंटे बाद कमजोरी, चक्कर, पसीने की शिकायत हो रही है तो

भूख, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना

सिरदर्द, भ्रम या चिड़चिड़ापन लक्षण कुछ खाने से अस्थायी रूप से ठीक हो जाते हैं.

वया करें?

अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे टाइम में क्या करें? सबसे पहले अपना नाश्ता बदलें, प्रोटीन + फाइबर + हेल्दी फैट वाला नाश्ता लें. अपनी डाइट में अंडे, सब्जियां, ग्रीक योगर्ट, नट्स, berries, पनीर परांठा, ओट्स, दाल, छाछ, मूंग स्पाउट्स को एड करें.

चावल, पास्ता

थायराइड के मरीजों को गलती से भी चावल, पास्ता जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. ग्लूटेन के सेवन को कम करना चाहिए. आंत में जलन पैदा कर सकता है और थायराइड हार्मोन की दवा का असर भी कम हो सकता है. इसलिए आपको कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए.

ब्रोकली, गोभी

ब्रोकली, गोभी जैसी सब्जियों का आपको कम से कम ही सेवन करना चाहिए. यह थायराइड हार्मोन के उत्पादन को तेजी से बढ़ा देता है. इसको खाने के बाद थायराइड की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है.

चीनी और प्रोसेस्ड फूड

आपको अपनी डाइट से चीनी और प्रोसेस्ड फूड को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए. ये हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है. इसको खाने के बाद आपके थायराइड का लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा. फिर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

इन चीजों के लिए भी कागरए

इसके अलावा, इस गोली को लेने वाले मरीजों में ब्लड प्रेशर भी बेहतर तरीके से कंट्रोल में पाया गया. रिसर्च का कहना है कि ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा भी सुधार लंबे समय में बड़े फायदे दे सकता है. स्टडी में यह भी सामने आया कि इस गोली से दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं, जैसे हार्ट अटैक और दिल की बीमारी से होने वाली मौत का खतरा भी कम हुआ. यानी यह इलाज सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, अभी कुछ सीमाएं भी हैं. इस स्टडी को कुछ सालों तक ही फॉलो किया गया है, इसलिए लंबे समय के असर को समझना बाकी है. इसके साथ ही, यह इलाज हर मरीज के लिए उपयुक्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

हमेशा एसी में रहने से बढ़ेंगी झुर्रियां और होगी रूखी त्वचा !

तेज गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोग घंटों तक एसी में समय बिताते हैं लेकिन लगातार एसी के इस्तेमाल से त्वचा पर कई तरह के असर देखने को मिल सकते हैं, जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से आपको स्किन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

कई बार इससे खुजली, जलन और जल्दी एर्जिंग के लक्षण भी दिखने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि एसी का इस्तेमाल करते समय स्किन की सही देखभाल की जाए और कुछ जरूरी सावधानियां अपनाई जाएं, ताकि ठंडक के साथ-साथ त्वचा भी स्वस्थ बनी रहे।

एसी त्वचा को कैसे प्रभावित करता है?

AC हवा में नमी कम कर देता है

एयर कंडीशनर कमरे की नमी को सोख लेता है, जिससे हवा बहुत ड्राई हो जाती है। इस ड्राई हवा के कारण त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है और धीरे-धीरे खिंचाव, रूखपन और असहजता महसूस होती है।

त्वचा के प्राकृतिक तेल कम हो जाते हैं

लगातार ठंडी हवा के संपर्क में रहने से स्किन के नेचुरल ऑयल बैलेंस पर असर पड़ता है। ये तेल त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग



बनाए रखते हैं, लेकिन इनके कम होने से स्किन बेजान, खुरदरी और डल दिखने लगती है।

3. झुर्रियां और फाइन लाइन्स जल्दी दिखने लगती हैं

ड्राई स्किन ज्यादा जल्दी एर्जिंग के संकेत दिखाती है। नमी की कमी से त्वचा की इलैस्टिसिटी कम होती है, जिससे फाइन लाइन्स और झुर्रियां समय से पहले नजर आने लगती हैं।

4. खुजली और जलन की समस्या

AC की ड्राई हवा स्किन की ऊपरी परत को इरिटेट कर सकती है। इसके कारण हल्की खुजली, जलन और कभी-कभी रेडनेस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

टि्कन को सुरक्षित रखने के उपाय

दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर और त्वचा दोनों हाइड्रेट रहते हैं। इससे स्किन की

नेचुरल चमक बनी रहती है और ड्राईनेस कम होती है।

एसी में रहने वाले लोगों को दिन में कम से कम 2 बार मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। यह त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर नमी को लॉक करता है।

लगातार लंबे समय तक एसी में रहने के बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में बाहर निकलकर शरीर को नॉर्मल नजर आने लगती है।

ह्यूमिडिफायर कमरे की नमी को बैलेंस करता है, जिससे एसी की ड्राईनेस का असर कम हो जाता है और स्किन को राहत मिलती है।

फेस मिस्ट या गुलाब जल

स्किन को तुरंत फ्रेश और हाइड्रेट करता है। दिन में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करने से स्किन में ताजगी बनी रहती है।

क्रैनबेरी खाने के क्या फायदे हैं? क्रैनबेरी जूस कितना असरदार है



क्रैनबेरी जूस को एक सुपरफूड ड्रिंक माना जाता है। इसे खासतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद बताया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर को कई तरह से

क्रैनबेरी का जूस पीने के क्या फायदे हैं?

क्रैनबेरी में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट की दीवारों पर चिपकने से रोकते हैं। इससे बार-बार होने वाले UTI का रиск कम हो सकता है। इसमें विटामिन C और

एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। क्रैनबेरी शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, जिससे किडनी और यूरिनरी सिस्टम बेहतर तरीके से काम करते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद कर सकता है, जिससे दिल की सेहत को सपोर्ट मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे त्वचा सॉफ और हेल्दी दिख सकती है।

बॉडी बनाने के लिए फाइबर को भूलकर सिर्फ ले रहे हैं प्रोटीन तो हो सकते हैं कैंसर के शिकार



आजकल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के ट्रेंड में ज्यादातर लोग सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देने लगे हैं. जिम शुरू करते ही डाइट में प्रोटीन शेक, चिकन, अंडे और सल्फोमेट्स की मात्रा बढ़ा दी जाती है, लेकिन इसी चक्कर में कई लोग फाइबर को लगभग भूल जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शरीर को सिर्फ प्रोटीन मिलेगा और फाइबर की कमी होगी, तो इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है.

वया फाइबर का ध्यान न रखने से हो सकती है दिक्कत?

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी फाइबर भी है. अगर हाई-प्रोटीन डाइट के साथ पर्याप्त फाइबर न लिया जाए, तो डाइजेशन सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है. इससे कब्ज, पेट फूलना, गैस और अनरगुलर बाउल मुवमेंट जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

हमारे शरीर के लिए फाइबर क्यों है जरूरी?

फाइबर सिर्फ पेट साफ रखने का काम नहीं करता, बल्कि यह आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मजबूत बनाता है. यही

बैक्टीरिया डाइजेशन को बेहतर रखने और शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. रिसर्च में यह भी सामने आया है कि जिन लोगों की डाइट में फाइबर ज्यादा होता है, उनका माइक्रोबायोम ज्यादा हेल्दी और विविध होता है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का खतरा कम हो सकता है.

फाइबर के बिना प्रोटीन क्यों नहीं करेगा काम

फाइबर भोजन के पाचन की गति को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. यही वजह है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से शरीर को पूरा फायदा नहीं मिल पाता.

एक एडल्ट को हर दिन कितना चाहिए फाइबर?

डॉ. का कहना है कि ज्यादातर एडल्ट को रोजाना करीब 25 से 35 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, लेकिन हाई-प्रोटीन डाइट फॉलो करने वाले कई लोग इस जरूरत का आधा भी पूरा नहीं कर पाते. दूसरी तरफ, कई लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं. आमतौर पर शरीर को रोजाना 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत

होती है, लेकिन हाई-प्रोटीन डाइट में यह मात्रा 80 से 90 ग्राम तक पहुंच सकती है.

कम फाइबर लेने वालों को कैंसर का भी खतरा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लंबे समय तक ज्यादा प्रोटीन और कम फाइबर वाली डाइट लेने से शरीर में सूजन, कब्ज और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. इतना ही नहीं, भविष्य में कोलन कैंसर और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है. खासतौर पर स्मोकड मीट और प्रोसेस्ड रेड मीट को ज्यादा मात्रा में खाने वालों में यह जोखिम अधिक माना गया है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि डाइट में सिर्फ प्रोटीन नहीं, बल्कि फाइबर से भरपूर चीजें भी शामिल करनी चाहिए.

कहां से मिलेगा शरीर को फाइबर?

फल, सब्जियां, ओट्स, चिया सीड्स, दालें, क्विनोआ और साबुत अनाज शरीर को जरूरी फाइबर देते हैं. इसके साथ ही फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिए और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, ताकि पेट से जुड़ी समस्याएं न हों.

थायराइड के मरीजों के लिए किसी जहर से कम नहीं ये चीजें

आजकल कम उम्र में ही लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बदलती लाइफस्टाइल हमारे शरीर पर काफी ज्यादा बुरा असर डाल रही है. आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के मरीजों की जिनको अपने खान-पान का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पुरुषों के मुकाबले महिलाएं थाइराइड की समस्या का सामना ज्यादा कर रही हैं. कुछ ऐसे फूड्स के बारे में आज हम इस खबर में बताते हैं, जिनका सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना लगाने पड़ सकते हैं डॉक्टर के चक्कर और आपकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है. आइए आपको बताते हैं.

थायराइड के मरीजों को कौन-कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

कैफीन

थायराइड के मरीजों को कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है.



थायराइड ग्रंथि और थायराइड के स्तर दोनों को काफी हद तक बढ़ा देती है और फिर समस्या और ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है.

फैटी फूड्स

अगर आप थायराइड के मरीज हैं और

अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको गलती से भी फैटी फूड्स जैसे मक्खन, मेयोनीज, मीट इन फूड्स का सेवन कम से कम करना चाहिए, वरना दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं.

दोबारा स्ट्रोक पड़ने का खतरा 40 पर्सेंट तक हो जाएगा कम

आज ही रोजाना खाना शुरू कर दें यह दवा

स्ट्रोक से बच जाना किसी भी मरीज के लिए बड़ी राहत की बात होती है, लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है. बहुत से लोग जो स्ट्रोक से उबर जाते हैं, उनमें दोबारा स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है. खासतौर पर उन मरीजों में यह जोखिम ज्यादा होता है जिन्हें दिमाग में खून बहने वाला स्ट्रोक यानी इंट्रोसेरेब्रल हेमरेज हुआ हो. चलिए आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या है.

क्यों होते हैं दोबारा स्ट्रोक?

इस तरह के स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है. जब लंबे समय तक हाई बीपी ज्यादा रहता है, तो खून की नसों की दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं. धीरे-धीरे यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि नस फट जाए और दिमाग में खून बहने लगे. इसलिए दोबारा स्ट्रोक से



बचने का सबसे असरदार तरीका है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना. हालांकि, यह काम उतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है. कई मरीजों को दिन में अलग-अलग समय पर कई तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं. खासकर बुजुर्गों या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह रूटीन निभाना मुश्किल हो जाता है. कभी दवा छूट जाती

है, तो कभी सही समय पर नहीं ली जाती, जिससे इलाज का असर कम हो जाता है.

इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक नई स्टडी की गई, जिसमें इलाज को आसान बनाने का तरीका खोजा गया. रिसर्च ने एक ऐसी गोली पर काम किया जिसमें ब्लड प्रेशर की तीन आम दवाइयों को कम मात्रा में मिलाया गया है. इस गोली का नाम

GMRx2 रखा गया है. यह स्टडी ट्रायल के तहत की गई, जिसमें अलग-अलग देशों के 1600 से ज्यादा मरीज शामिल हुए. ये सभी मरीज पहले दिमाग में खून बहने वाले स्ट्रोक का सामना कर चुके थे और उनका ब्लड प्रेशर अभी भी सामान्य स्तर से ऊपर था.

मरीजों को दो समूहों में बांटा गया. एक समूह को यह नई कॉम्बिनेशन गोली दी गई, जबकि दूसरे समूह को सामान्य इलाज के साथ प्लेसीबो दिया गया. इसके बाद दोनों समूहों के परिणामों की तुलना की गई. नतीजे काफी चौकाने वाले रहे. जिन मरीजों ने यह कॉम्बिनेशन गोली ली, उनमें दोबारा स्ट्रोक का खतरा करीब 40 प्रतिशत तक कम हो गया. यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि दोबारा स्ट्रोक अक्सर ज्यादा गंभीर साबित होता है.

बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर पीएम ने जताई खुशी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दो इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य केंद्र की प्रमुख योजना को लागू करेगा, जिसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। आगे कहा कि डबल इंजन वाली सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

हमारे आंतरिक मामले में भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों: प्रियांक बेंगलुरु

प्रियांक खरो ने मंगलवार को भाजपा द्वारा केरल के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में देरी को लेकर उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया। विधानसभा चुनावों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की शानदार जीत के बाद से जारी गतिरोध को देखते हुए उन्होंने इसे गठबंधन का आंतरिक मामला बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर इस मामले पर सवाल उठाने के लिए हमला बोला और कहा कि पार्टी को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाने में एक महीना लग गया। खरो ने कहा कि भाजपा को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? उन्हें कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाने में एक महीने से ज्यादा का समय लगा। यह हमारा आंतरिक मामला है। यह घटना भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करने के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की योजना पांच साल में राज्य को पांच मुख्यमंत्री देने की प्रतीत होती है।

पश्चिम बंगाल में नियुक्ति पर राहुल का भाजपा पर तंज

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की आलोचना की, जब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। एक फेसबुक पोस्ट साझा करते हुए, कांग्रेस संसद ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए लिखा कि भाजपा-चुनाव आयोग के 'चोर बाजार' में - जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम। सोमवार को भाजपा सरकार ने मनोज कुमार अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल मनोज कुमार अग्रवाल (एएस (डब्ल्यूबी :1990), मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल, और पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं पर्वतीय मामलों (चुनाव) विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त करते हैं।

तमिलनाडु में मंदिर-स्कूलों के पास अब नहीं बिकेगी शराब

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य भर में मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) द्वारा संचालित इन दुकानों को दो सप्ताह के भीतर बंद करना होगा। यह आदेश सप्तारूढ़ तमिलगा वेट्टी कज्जम (टीवीके) के नेता का पहला आदेश है, जिसने पिछले महीने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। इसमें कहा गया है कि आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने आदेश जारी किया है कि पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 खुदरा शराब की दुकानें दो सप्ताह के भीतर बंद कर दी जाएं। सरकार ने बताया कि वर्तमान में TASMAC राज्य में 4,765 शराब की दुकानें संचालित करता है, जिनमें से 276 पूजा स्थलों के पास, 186 शैक्षणिक संस्थानों के पास और 255 बस स्टैंडों के पास स्थित हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि के विवादित बोल

चेन्नई। विपक्ष के नेता और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा में सनातनवाद विरोधी माहौल को फिर से जीवंत कर दिया। उन्होंने इसके उन्मूलन की मांग को भी दोहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सनातनवाद, जिसने लोगों को विभाजित किया, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। उदयनिधि ने आगे कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री को हमारे नेता और कई अन्य नेताओं से शुभकामनाएं मिलीं। यह राजनीतिक शिष्टाचार इस सदन में भी जारी रहना चाहिए। भले ही हम सत्ताधारी और विपक्ष के रूप में अलग-अलग पंक्तियों में बैठे हों, हम सभी को तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उदयनिधि ने कहा कि विपक्षी दलों ने वंदे मातरम के बाद तमिलनाडु राज्य गीत बजाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं बजाया गया था।

असम में हिमंता बिस्वा सरमा की ताजपोशी

पीएम मोदी बोले- आप एक उत्कृष्ट प्रशासक हैं

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमंता बिस्वा सरमा को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और उनके नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं की प्रशंसा की। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि असम के लिए एक गौरवशाली दिन! लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार ने पदभार ग्रहण किया है। डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा जी को शपथ ग्रहण पर हार्दिक बधाई। उन्होंने एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और राज्य के लिए अग्रणी कार्य किए हैं। आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त मंत्रियों रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अर्जुना नियोग को भी बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि वे असम के विकास पथ को मजबूत करने में योगदान देंगे।

प्रधानमंत्री के संदेश का जवाब देते हुए, सरमा ने शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि पिछले एक दशक में असम के विकास में उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरमा ने कहा कि आपका मार्गदर्शन हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत रहा है। आपके नेतृत्व और दूरदृष्टि ने ही हमें सेवा और समर्पण के मार्ग पर अग्रसर किया है। इस क्षण को भावुक बताते हुए सरमा ने कहा कि असम के मुख्य सेवक के रूप में अपनी शपथ की पुष्टि करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्होंने जनता के कल्याण और आकांक्षाओं के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और असम की जनता के आशीर्वाद से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर हम जनता की सेवा करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शाह राज्य में शांति और समृद्धि बहाल करने के प्रयासों में चट्टान की तरह खड़े रहे। सरमा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और असम भर में एनडीए कार्यकर्ताओं को गठबंधन की चुनौती सफलता में योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी मंत्री सदस्यगियों को बधाई भी दी और विकसित और सुरक्षित असम के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।



अमेरिका की नजर अब नार्थ ईस्ट पर, असम के साथ नई पाटनरशिप को तैयार

सर्जियो गोर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका असम के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम करेगा, और दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाने वाली वाणिज्यिक साझेदारियों के विस्तार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। गोर गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता और राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर राजनीतिक इतिहास रचा है। समारोह के बाद सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए गोर ने कहा कि उन्हें इस अवसर पर गुवाहाटी आमंत्रित किए जाने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और असम के बीच पहले से ही कई वाणिज्यिक संबंध हैं और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरमा के नेतृत्व में दोनों पक्ष भविष्य में पारस्परिक रूप से लाभकारी कई और अवसरों की पहचान कर सकेंगे।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने मंगलवार को असम में नवगठित भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हार्दिक बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि राज्य अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। सरमा के अलावा, चार अन्य मंत्रियों ने भी नए मंत्रिपरिषद में शपथ ली।

सेंसेक्स 1,456 अंक गिरा निफ्टी 23,400 के नीचे

नईदिल्ली। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1,456.32 अंक (1.92%) गिरकर 74,558.96 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 454.15 अंक (1.91%) टूटकर 23,361.70 पर आ गया। दिनभर के कारोबार में निवेशकों की लगभग 9.6 से 10 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति खत्म हो गई, क्योंकि बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। बाजार गिरने की मुख्य वजहें थीं-कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर (95.58) पर पहुंचना और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव। इन कारणों से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और बाजार पर दबाव बढ़ गया। विदेशी मुद्रा भंडार में ज्यादा तेल जरूरतें आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

मूडीज ने घटाया भारत की ग्रोथ का अनुमान

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कटौती की है। एजेंसी ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह अनुमान इससे अधिक था। एजेंसी का कहना है कि निजी खपत में सुस्ती, निवेश गतिविधियों में धीमापन और औद्योगिक उत्पादन पर दबाव के चलते आर्थिक वृद्धि की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। मूडीज ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट के मई अपडेट में कहा है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतों का असर आने वाले महीनों में कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन, उर्वरक और ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति में आने वाली दिक्कतें आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं।

शुरुआती तेजी के बाद सोना-चांदी में आई गिरावट

नईदिल्ली। भारत में मंगलवार, 12 मई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में शुरुआत में तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में दोनों की कीमतें गिरावट के साथ कारोबार करने लगीं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर बुलियन मार्केट पर साफ दिखाई दिया। मल्टी कम्पिडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना शुरुआती कारोबार में 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन बाद में इसकी बढ़त खत्म हो गई। दोपहर तक एमसीएक्स गोल्ड करीब 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं एमसीएक्स ने शुरुआती कारोबार में करीब 1.2% की तेजी के साथ 2.82 लाख रुपये का स्तर छुड़ा, लेकिन बाद में इसमें तेज गिरावट आई। इसके बाद चांदी करीब 1.5% टूटकर 2.74 लाख रुपये के आसपास कारोबार करने लगी।

दबाव के बावजूद केनरा बैंक पर बढ़ा भरोसा!

नईदिल्ली। केनरा बैंक के तिमाही नतीजों में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। पहली इनक में मुनाफा घटा हुआ दिखाता है। ट्रेजरी इनकम कमजोर रही और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी दबाव नजर आया। लेकिन इसके बावजूद बैंक को लेकर एक्सपर्ट्स का भरोसा कमजोर नहीं पड़ा। दरअसल, कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है। असली फोकस इस बात पर है कि बैंक की कार बिजनेस ग्रोथ कैसी है, लोन बुक कितनी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में कमाई की रफ्तार कैसी रह सकती है। यही वजह है कि मिक्सड क्वार्टर के बावजूद कई ब्रोकरेज हाउस अब भी केनरा बैंक को लेकर बुलिश बने हुए हैं। मार्च तिमाही में केनरा बैंक का शुद्ध मुनाफा करीब 4,500 करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर इसमें करीब 10 फीसदी की गिरावट आई।

स्टेल प्रमुख समाचार

बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मुकाबला आज

रायपुर। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 13 मई को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ अहम मुकाबला खेलना है। रायपुर की पिच पिछले मैच में स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुई थी। ऐसे में अगर वरुण चक्रवर्ती इस मैच से बाहर होते हैं तो यह केकेआर के लिए बड़ा नुकसान होगा। एक केकेआर सूत्र ने कहा, वरुण सोमवार को टीम के प्रैक्टिस सेशन में मौजूद था, लेकिन आरसीबी मैच में उनकी उपलब्धता पर फैसला मंगलवार को लिया जाएगा।

केकेआर की स्पिन गेंदबाजी काफी हद तक सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती पर निर्भर करती है। दोनों मिडिल ओवरस में रन रोकने और विकेट निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर वरुण बाहर होते हैं तो अनुकूल रॉय को पूरे चार ओवर फेंकने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कैमरून ग्रीन पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। टीम के पास विकलक्ष के तौर पर लेग स्पिनर प्रशांत सोलंकी और दक्ष कामरा मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है।

34 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती का आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 11 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका औसत 19.93 और इकॉनमी रेट 7.17 रहा है। उन्होंने एक बार चार विकेट भी झटक हैं। आईपीएल 2026 की शुरुआत वरुण के लिए ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार वापसी की। फुट इंजरी के कारण कुछ मैच मिस करने के बावजूद उन्होंने 8 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 8.62 रहा। केकेआर ने लगातार चार जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं, लेकिन अब सबकी नजर वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस पर टिकी हुई है।

सनत जैन

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले ढाई महीनों में तेजी से घटकर लगभग 550 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। यह स्थिति केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए चिंता का विषय है। विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। इसी के सहारे आयात, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखने में होता है। इसका असर आयात और निर्यात दोनों पर पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच जब युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में वैश्विक बाजार में अस्थिरता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर की मजबूती के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट भारत की अर्थ व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का संकेत है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का

85 फीसद हिस्से का आयात करता है। खाद भी बड़े पैमाने पर भारत को आयात करनी होती है। पेट्रोलियम, खाद और गैस के आयात में भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी सरकार और रिजर्व बैंक को वैकल्पिक उपायों पर विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉलर बॉन्ड जारी करने की योजना सामने आई है। विदेशों में बसे भारतीयों (एनआरआई) को बांड बेचकर सरकार डॉलर का भंडार बढ़ाना चाहती है। यह योजना सरकार और रिजर्व बैंक के लिए अल्पकालिक राहत देने वाली होगी। एनआरआई निवेशकों से डॉलर प्राप्त कर सरकार विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने का प्रयास करेगी। इससे तत्काल डॉलर की उपलब्धता बढ़ सकती है। रुपये पर पड़ रहा



दबाव कुछ कम हो सकता है। भारत वित्तीय स्थिति को तत्काल नियंत्रित करने में सफल हो सकता है। लेकिन आगे चलकर अर्थव्यवस्था में दोहरा दबाव भी पड़ सकता है। इस योजना के साथ कई जोखिम भी हैं। सबसे बड़ा खतरा विनिमय दर का है। पिछले कुछ वर्षों में डॉलर, लगातार रुपये के मुकाबले मजबूत हुआ है। भविष्य में रुपये की कमजोरी जारी रहती है, तो सरकार को बॉन्ड का भुगतान मांग के अनुसार करने पर ज्यादा डॉलर भुगतान करना पड़ेगा। इसमें सरकार को केवल ब्याज ही नहीं, बल्कि विनिमय दर में भी नुकसान उठाना पड़ सकता

है। यह स्थिति भविष्य में वित्तीय दबाव को और बढ़ा सकती है। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए केवल उभारी आधारित समाधान लंबे समय तक प्रभावी नहीं हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है, भारत को निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने, घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में ज्यादा ध्यान देना होगा। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में दीर्घकालीन ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। सरकार और रिजर्व बैंक को समझना होगा, विदेशी मुद्रा भंडार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह देश के आयात-निर्यात भुगतान के संतुलन तथा आर्थिक विश्वसनीयता का प्रतीक है। यदि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है तो उसे संभालने के लिए बार-बार बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह दीर्घकालिक

आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए डॉलर बॉन्ड तत्काल महमम का काम कर सकता है। यह स्थायी समाधान नहीं है। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को बेहतर एवं मजबूत बनाना होगा। विदेशी मुद्रा भंडार आयात-निर्यात भुगतान संतुलन एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का भंडार होना ही चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से देश को अर्थ संकट का सामना कर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। विदेशी निवेशक भारत से भाग रहे हैं। निर्यात की तुलना में आयात लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार के ऊपर देसी और विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में गंभीरता के साथ सरकार के अर्थ विशेषज्ञों और रिजर्व बैंक को जवाबदेही के साथ जिम्मेवारी का निवाह करना होगा, अन्यथा स्थिति कभी भी भयावह हो सकती है।

रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से बदल रही तस्वीर

छग में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम

रायपुर। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक आजीविका, स्थायी आय और आत्मनिर्भरता से जोड़ना रही है। यही कारण है कि खेती, वनोपज, स्वरोजगार और लघु उद्यमों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत किया है।

प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए किसानों, ग्रामीणों और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में



महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि केवल बेरोजगारी के आंकड़े कम होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच के अनुरूप कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और निवेश आधारित

औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जहां प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसरों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और रोजगारोन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान और अधिक सुदृढ़ करेगा।

टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जपाइगो के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर स्थित निजी होटल में टीबी रोग संबंधी राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में डिफरेंशिएटेड टीबी केयर, गर्भवती महिलाओं में टीबी प्रबंधन तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में टीबी सेवाओं के समन्वय विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं श्री संजीव झा ने प्रतिभागियों को भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के टीबी मुक्त भारत के संकल्प की याद दिलाते हुए जमीनी स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि



■ रायपुर में स्वास्थ्य अधिकारियों को डिफरेंशिएटेड टीबी केयर, गर्भवती महिलाओं में टीबी प्रबंधन एवं टीबी सेवाओं के समन्वय की दी गई जानकारी

टीबी के संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच कर टीबी की पुष्टि होने पर उन्हें डिफरेंशिएटेड टीबी केयर के अंतर्गत अनिवार्य रूप से श्रेणीबद्ध कर उपचार उपलब्ध कराया जाए। कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय अभियान की जिलेवार समीक्षा भी की गई। राज्य क्षय अधिकारी डॉ. संजीव मेश्राम ने जिला क्षय अधिकारियों को टीबी मरीजों के

संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को शत-प्रतिशत टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने तथा मरीजों को अतिरिक्त सहयोग देने के लिए अधिकाधिक निक्षेय मित्र बनाने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधिकारी, विभिन्न जिलों के जिला क्षय अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला पीएमडीटी समन्वयक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक में 67 समिति

प्रबंधकों की भर्ती को मिली हरी झंडी

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र संवर्ग) के शेष 67 पदों पर भर्ती मोदी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रदेश की सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में रिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है।



पदभार ग्रहण करते ही आयुक्त महादेव कावरे का बड़ा निर्णय सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री महादेव कावरे ने कार्यभार संभालते ही प्राथमिकता के आधार पर अपेक्स बैंक के रायगढ़ और जशपुर क्षेत्र के लिए संवर्ग समिति प्रबंधक (नवीन

की अनुमति प्रदान कर दी है। कुल स्वीकृत पद अपेक्स बैंक में संवर्ग समिति प्रबंधक के कुल 134 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 67 पदों पर भर्ती की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी थी। अब शेष 67 पदों के लिए भी अनुमति जारी कर दी गई है, जिससे कुल स्वीकृत पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस नई भर्ती से राज्य की पैक्स और लैम्प्स समितियों की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार आएगा। कम्प्यूटीकरण से समितियों में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। किसान सुविधा में विस्तार होगा और सदस्य किसानों को ऋण, खाद-बीज और अन्य सहकारी सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल सकेंगी।

महापौर मीनल चौबे ने किया कलाकेन्द्र

का निरीक्षण, शिक्षकों से की भेंट

■ स्वीमिंग पुल के संधारण एवं नालंदा परिसर की दुकानों पर भी हुई चर्चा

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने आज जिला प्रशासन द्वारा संचालित कलाकेन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां विविध सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलाकेन्द्र का संचालन गुणवत्ता और श्रेष्ठता के साथ जनहित में किया जाए। उन्होंने कलाकेन्द्र में विविध सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके पश्चात महापौर ने इंटरनेशनल स्वीमिंग पुल की व्यवस्था का निरीक्षण किया।



उन्होंने स्वीमिंग पुल का अच्छी तरह संधारण सहित संचालन जनहित में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही नालंदा परिसर के समीप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में निर्मित दुकानों के संबंध में जिला एवं जोन-7 के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पटेल को आवश्यक निर्देश दिए।महापौर ने कलाकेन्द्र, इंटरनेशनल स्वीमिंग पुल एवं नालंदा परिसर की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधि एवं जोन-7 के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

देशवासियों से अपील जख्मों पर नमक डालने का काम: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कल देशवासियों से की गयी अपील ने देशवासियों के जख्मों पर नमक डालने का काम किया। पिछले 2 माह से डीजल, पेट्रोल, गैस के संकट से जूझ रही तथा महंगाई की मार झेल रहे लोगों से प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों को सलाह दिया कि खेती में उर्वरक का उपयोग कम करें। उन्होंने देश के कामकाजी वर्ग को सलाह दिया कि वर्क फॉर्म होम करिए। ऑफिस मत जाइये। उन्होंने देश की महिलाओं को सलाह दिया खाद्य तेल कम उपयोग करे, गैस का उपयोग कम करे। उन्होंने देशवासियों से कहा सोना मत खरीदे। उन्होंने लोगों से कहा विदेश यात्रा मत करे।

उर्वरक नहीं मिलने पर किसानों की उत्पादकता घट रही। मोदी कह रहे कि किसान उर्वरकों का उपयोग कम करें जबकि देश में पिछले सात साल से उर्वरकों की कमी है। प्रधानमंत्री उर्वरक की व्यवस्था करने के बजाय बार-बार किसानों से यूरिया की खपत कम करने की अपील करते रहे हैं। किसानों की आय दुगुनी करने का वादा था लेकिन उर्वरक नहीं मिलने तथा महंगा उर्वरक खरीदने के कारण किसान कर्जदार हो रहे, उत्पादकता घट रही।

आईपीएल मुनाफा कमाने का आयोजन: शुक्ला

रायपुर। आईपीएल विशुद्ध रूप से व्यावसायिक आयोजन है, पैसा कमाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिये लाखों रुपये राजस्व बीसीसीआई कमा रहा है। उसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुफ्त में सुविधा उपलब्ध कराना आपत्तिजनक है। यह जनता के धन की बर्बादी है, कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। करोड़ों रुपये खर्चा करके कांग्रेस की पहली सरकार ने शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको सुरक्षित नहीं रख पाई और बीसीसीआई को सौंप दी। बीसीसीआई को सौंपे तो ठीक करें, उसके बदले में बीसीसीआई से राज्य के लोगों के लिये और राज्य के खिलाड़ियों के लिये क्या सहूलियत दी है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये। आईपीएल में जितनी भी सुविधायें दी जा रही हैं, बिजली की सुविधा दी जा रही, पानी की सप्लाई दी जा रही है, वहां पे पुलिस फोर्स लगाये गये हैं, सुरक्षार्कमी लगाये गये हैं, सफाई कर्मी लगाये गये हैं। प्रशासन के लोगों की ड्यूटी है, सरकारी अधिकारी व्यवस्था देख रहे हैं। बदले में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा हो रहा है? सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिये?

नीट पेपर लीक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़: वर्मा

रायपुर। पेपर लीक के चलते 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है। भाजपा शासित राज्यों में शिक्षा माफिया को संरक्षण देकर पेपर लिख करवाए जाते हैं जिसका भुगतान छात्रों को भुगतान पड़ता है। बार-बार परीक्षाओं में धांधली से एनटीए की विश्वसनीयता, कार्यक्षमता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पिछली बार भी नीट के पेपर लीक मामले में मोदी सरकार ने किसी की जवाबदेही तय नहीं की, न ही कोई ठोस कार्यवाही किया था। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, लाखों बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई थी, तब लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए मोदी सरकार ने चाल चली और एनटीए के डीजी को पद से हटा दिया, लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ, इन्हें स्टील मिनिस्ट्री में पोस्टिंग दे दी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं का प्रमुख बना दिया और अब ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। बेहद स्पष्ट है कि पेपर लीक के असल गुनहवारों को भाजपा सरकार का संरक्षण है।

सोना नहीं खरीदने की अपील के समर्थन में उतरा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि सराफा व्यापारियों को इस मुद्दे पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कदम दीर्घकाल में देश की अर्थव्यवस्था और सराफा व्यापार दोनों को मजबूती प्रदान कर सकता है।कमल सोनी ने कहा कि पिछले दो वर्षों से वैश्विक युद्ध, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता और बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर सराफा कारोबार पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सामान्य आभूषण व्यापार लागभग सीमित होकर केवल बुलियन आधारित लेन-देन तक सिमट गया है, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि लगातार मूल्य अस्थिरता के कारण व्यापारियों को नुकसान और कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री की यह अपील भविष्य में व्यापक आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई को

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के लिए कुल 33 जिलों से 1एक 37 लाख 323 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण के बाद कुल 63 हजार 342 अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त हैं। शारीरिक माप परीक्षण के बाद अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 (रविवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 33 जिले में केन्द्र बनाए गए हैं। सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/ प्लाटून कमांडर के पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए जिला सरगुजा , कोरिया , बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दंतवाड़ा, बस्तर , जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवर्धा, उत्तर बस्तर कोंडर को केन्द्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार कोरबा, महासमुन्द्र, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर- रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, जमेतरा, बालोद, गौहला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्की, सारांगढ़-बिलाईगढ़ को परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार/ उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।

कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक का शुभारंभ

खरपतवारनाशकों के दुष्प्रभाव का करें अध्ययन : डॉ. नायक

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज यहां अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना की 33वीं वार्षिक समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई। इस तीन दिवसीय बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉ. ए. के. नायक द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल ने की। वैशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, (आईसीएआर) बरौड़ा रायपुर के निदेशक डॉ. पी. के. राय तथा डॉ.



राकेश कुमार सहायक महानिदेशक आईसीएआर नई दिल्ली मौजूद थे। यह परियोजना देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर अनुसंधान तथा नवीनतम तकनीकों के विकास एवं उनके किसानों के बीच प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा जबलपुर स्थित खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से चलाई जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए

मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. नायक ने वैज्ञानिकों से खरपतवारों के रसायनिक नियंत्रण के बजाय समन्वित खरपतवार नियंत्रण को अपनाते पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशकों के हानिकाकरक प्रभावी को देखते हुए उन पर आधारित अनुसंधान को हतोत्साहित किया जाए। डॉ. नायक ने प्राकृतिक एवं जैविक कृषि अपनाने पर जोर देते हुए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों,

केंचुओं तथा कीट पतंगों पर खरपतवारनाशकों के दुष्प्रभाव का अध्ययन करने की सलाह दी। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल ने कहा कि रासायनिक खरपतवारनाशी यद्यपि खेतों में खरपतवारों के नियंत्रण करने में समर्थ है लेकिन ये पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है अतः इनका नियंत्रित और प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए। खरपतवार नाशकों का अंधाधुंध उपयोग मानवों और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खरपतवारों के प्रबंधन के लिए केवल रसायनों पर निर्भर न रहकर

यांत्रिक एवं बायोलॉजिकल नियंत्रण विधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समारोह को डॉ. पी. के. राय तथा डॉ. राकेश कुमार ने भी संबोधित किया। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर के प्रभारी डॉ. विजय कुमार चौधरी, प्रमुख वैज्ञानिक ने अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार प्रबंधन अनुसंधान परियोजना के तहत देशभर के सभी 17 केन्द्रों में संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर परियोजना के वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 के साथ ही अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया।

नर्सिंग सिस्टर अब कहलाएंगी

सीनियर नर्सिंग ऑफिसर

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सस दिवस पर राज्य की नर्सों के सम्मान में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तन की बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी जबकि *स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सस दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये घोषणा की है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी व नर्सिंग छात्र-छात्राओं के साथ अस्पताल के अन्य अधिकारी एवं



कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भूमिका की सेवा में नर्सों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो दिन-रात समर्पण भाव से मरीजों की देखभाल कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा में मानवीय संवेदनाओं और सेवा भाव का

सबसे बड़ा उदाहरण नर्सिंग स्टाफ प्रस्तुत करता है। उन्होंने कोविड काल में नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं की याद करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी नर्सों ने समर्पण और सेवा भाव के साथ कार्य किया। चिकित्सा सेवा में नर्स माँ के समान उच्च है क्योंकि वे मरीजों की देखभाल परिवार की तरह करती हैं।